

जन जन की बात जन जन तक

साप्ताहिक

जन जन विचार



WEEKLY TRILINGUAL NEWSPAPER

Language : Hindi, Assamese & English

WEBSITE : www.janjanvichar.in

বাইজৰ কথা বাইজৰ মাজলৈ

সাপ্তাহিক

জন জন বিচাৰ

VOICE OF ALL, FOR ALL

WEEKLY

JAN JAN VICHAR

RNI Regd No. ASMUL/25/A2367::Guwahati, Friday, 25 September 2026 :: Year-1 Vol-37 Issue-16 :: शुक्रवार। 25 सितंबर 2026। शक संवत 1948। भाद्रपद। शुक्ल। चतुर्दशी। :: पृष्ठ-20। मूल्य - 15 रुपए



जन चिंतन — धनेश्वर चौधरी

कानून 'ढाल' बने 'हथियार' नहीं

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम उस ऐतिहासिक अन्याय की प्रतिक्रिया है, जिसे वंचित समुदायों ने पीढ़ियों तक झेला है। इस कानून की जरूरत और उसकी कठोरता से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल कहीं और है-क्या जिस कानून से कमजोर को सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसके इस्तेमाल के साथ व्यवस्था की जवाबदेही भी उतनी ही मजबूत है?

आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत ने इस सवाल को फिर देश के सामने ला खड़ा किया है। 18 सितंबर को परीक्षा के दौरान साहिल के मोबाइल इस्तेमाल का मामला सामने **शेष पृष्ठ 2 पर**

नगांव उपचुनाव : हिमंत का कांग्रेस पर तंज

गुवाहाटी। नगांव लोकसभा उपचुनाव को लेकर असम में सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने चुनावी सभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि पार्टी आगामी उपचुनाव हार जाती है तो वह अगले 100 वर्षों तक नगांव लोकसभा सीट से बाहर रह सकती है। हालांकि यह मुख्यमंत्री का राजनीतिक दावा है, चुनाव के परिणाम के बारे में स्वतंत्र रूप से कोई निष्कर्ष अभी नहीं निकाला जा सकता।

शर्मा ने भाजपा के लिए समर्थन जुटाते हुए कहा कि पार्टी धार्मिक आधार पर राजनीति नहीं करती और उसे सभी समुदायों से समर्थन मिलने की उम्मीद है। उन्होंने दावा किया कि पिछले चुनावों में 'मियां' समुदाय के एक वर्ग ने भी भाजपा का समर्थन किया था।

कटघरे में चुनाव आयोग

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

भारत में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता का सबसे बड़ा आधार हैं। यही वजह है कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और निर्णय प्रक्रिया पर उठने वाला हर सवाल व्यापक महत्व रखता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और आयोग के कुछ फैसलों को लेकर चल रही राजनीतिक तथा कानूनी बहस ने एक बार फिर निर्वाचन आयोग की भूमिका को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

ताजा घटनाक्रम में महाराष्ट्र की एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े मामलों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल हुई हैं। इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल के पिछले करीब 10 महीनों के 14 प्रशासनिक फैसलों को चुनौती दिए जाने का दावा किया गया है। याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि दो चुनाव आयुक्तों ने इनमें आपत्ति जताई थी। मामले पर 28 सितंबर को सुनवाई संभावित है। **शेष पृष्ठ 7 पर**



सवाल सिर्फ आज के नहीं हैं

निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में हुई। शुरुआती दशकों में आयोग एक-सदस्यीय था। 1989 में पहली बार दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए, हालांकि यह व्यवस्था कुछ समय बाद समाप्त कर दी गई। अक्टूबर 1993 से आयोग स्थायी रूप से बहु-सदस्यीय ढांचे में काम कर रहा है। आज मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त मिलकर आयोग के निर्णय लेते हैं। व्यवस्था में निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। यही बहु-सदस्यीय व्यवस्था 1990 के दशक में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन और केंद्र सरकार के बीच विवाद का कारण भी बनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में बहु-सदस्यीय आयोग और समान शक्तियों की व्यवस्था को बरकरार रखा।

'वोट की चोरी नहीं चलेगी, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें'

जन जन विचार
...✍ मधुबनी

बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता, खगड़िया जिला संगठन सृजन प्रभारी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कृष्ण कांत झा 'गुड्डू' ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर उठे विवाद और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से इस्तीफे की मांग



करते हुए कहा कि मतदाता और उसके मताधिकार से जुड़े सवालों पर अब केवल सफाई नहीं, बल्कि जवाबदेही तय होनी चाहिए।

गुड्डू ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले तीन वर्षों से चुनाव प्रक्रिया और कथित 'वोट चोरी' से जुड़े सवाल उठाते रहे हैं। 24 सितंबर को राहुल गांधी ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाते हुए निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली **शेष पृष्ठ 7 पर**

कुल्हाड़ियों की छांव में जंगल

ललित निबंध

जन जन विचार

...✍ डॉ मुकेश कुमार

गतांक से आगे...

मानव जाति की इस विवेकहीन अंधी लालसा ने प्रकृति के उस अद्भुत, सुगठित और दिव्य संतुलन को तिनका-तिनका करके पूरी तरह बिखेर कर रख दिया है, जिसे रचने और सहेजने में इस ब्रह्मांड ने न जाने कितने ही युग और लाखों वर्ष लगाए थे। जब हरी-भरी पहाड़ियों के विशाल जंगल बेदर्दी से काटे गए, तो कल-कल बहती नदियों के प्राकृतिक मार्ग बाधित होकर बदलने लगे। नदियां जैसे ही सिमटकर गंदे नालों में तब्दील हुईं, वैसे ही स्वच्छ हवा में नमी की जगह जहरीले रसायनों का धुआँ



घुलने लगा। आज जब हम महानगरों की बहुमंजिला इमारतों की सजी-धजी बालकनी में खड़े होकर गरमा-गरम चाय की चुस्की लेते हैं, तो चारों ओर फैला हुआ जहरीला धुआँ हमें यह अहसास ही नहीं होने देता कि हम अपनी प्रत्येक साँस के साथ प्रकृति का एक जीवंत कतरा निरंतर निगल रहे हैं। आसमान का वह गहरा प्राकृतिक नीला रंग, जिसे देखकर कभी युगीन कवियों की कोमल कल्पनाएँ मचल उठती थीं, अब एक जहरीली धुंध और काली परत के पीछे सदा के लिए छिप गया है। रात्रि के समय आकाश के अनगिनत चमकीले तारे अब बच्चों के साथ आँख-मिचौनी का खेल नहीं खेलते, क्योंकि जमीन का बनावटी जहरीला प्रकाश और भीषण वायु प्रदूषण उन्हें हमारी नग्न आँखों की पहुँच से बहुत दूर ढकेल चुका है।

पहाड़ों की तरफ कातर नजरों से उठाकर देखिए तो वहाँ का दारुण क्रंदन और भी अधिक भयावह तथा हृदयविदारक प्रतीत होता है। जो गगनचुंबी पहाड़ कभी परम शांत, गंभीर और धवल बर्फ की सुंदर चादर ओढ़े किसी सिद्ध तपस्वी की भाँति युगों-युगों से निश्चल खड़े रहते थे, आज वे भी अंदर तक कराह रहे हैं। बड़े-बड़े व्यावसायिक रिसॉर्ट्स, चौड़ी राष्ट्रीय सड़कों और डायनामाइट के भयंकर गूँजते धमाकों ने उन मौन ऋषियों की छाती को बेदर्दी से चीर कर रख दिया है। देवदार, साल और चीड़ के वे ऊँचे वृक्ष, जो कल तक नीले बादलों के संग आत्मीय गुफ्तगू किया करते थे, आज बेदर्दी से कटकर गाड़ियों की छतों पर बेजान लादे जा रहे हैं। जब भीषण भूस्खलन में विशाल पहाड़ धसकते हैं, तो वह केवल साधारण मिट्टी और पत्थरों का गिरना मात्र नहीं होता, बल्कि वह कुपित प्रकृति का वह भयानक हाहाकार होता है जो वह हमारी निरंतर बढ़ती उद्दंडता और अनैतिक हस्तक्षेप के जवाब में करती है। परंतु हम मानव इतने संवेदनहीन और बेखबर हो चुके हैं कि तबाही के उस भयानक मलबे के ऊपर भी एक नया कंक्रीट का बहुमंजिला ढाँचा खड़ा करने की अंधी जल्दी में रहते हैं।

धरती के इन बेजुबान जीव-जंतुओं की व्यथा-कथा का तो कहना ही क्या! जिस सुंदर धरती पर उनका भी उतना ही नैसर्गिक और नैतिक अधिकार था जितना कि हमारा, उन्हें हमने पूर्णत: बेघर और असहाय कर दिया है। वह नन्ही गौरैया, जो कभी हमारी रसोई की खिड़की पर निडर होकर बैठती थी, चावल के दानों को चुगती थी और अपनी कोमल चोंच की मधुर चहचहाहट से पूरे घर को सजीव तथा आनंदित कर देती थी, आज ढूँढे से भी नहीं मिलती। कहाँ लुप्त हो गई वे चितकबरी तितलियाँ जिनके सतरंगी पंखों के पीछे हम बाल्यकाल में नंगे पैर खेतों और बगीचों में भागते थकते नहीं थे? कहाँ खो गए वे मखमली जुगनू जो अंधेरी रातों में पेड़ों की डालियों पर सितारों का पूरा कारवाँ उतार लाते थे? हमने अपने घरों में बिजली के चमचमाते आधुनिक बल्ब तो टाँग लिए, किंतु उस नन्हें जुगनू की सात्विक और प्राकृतिक रोशनी को हमेशा के लिए खो दिया जो हमारे संवेदनशील हृदय में एक अव्यक्त रहस्यमयी खुशी भर देती थी। अब जंगल के जंगली जानवर इंसानी बस्तियों में भटकने पर विवश हैं, इसलिए नहीं कि वे हम पर हमला करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हमने उनके पुरखों के घर छीन लिए हैं। जब वे अपने ही प्राचीन घर की बची-कुची सीमाओं पर भटकते हुए आते हैं, तो हम उन्हें हिंसक 'खतरा' घोषित करके मार डालते हैं।

पावन जल के बिना तो इस धरा पर जीवन का अंकुरण और संचालन ही असंभव है, किंतु अपनी असीम अज्ञानता में हमने अपने ही जीवनदाता जल-स्रोतों को जहरीले कचरे का ढेर बना दिया है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा जैसी नदियाँ, जिनके पुण्य तटों पर महान भारतीय संस्कृतियों ने जन्म लिया था, आज अपने ही संकटग्रस्त अस्तित्व के लिए करुण गुहार लगा रही हैं। नदियों का वह कल-कल बहता हुआ पवित्र और निर्मल जल, जो आचमन करने मात्र से मन-प्राण को शुद्ध कर देता था, आज कारखानों के विषैले रसायनों का काला नाला बन चुका है।

जारी...

पृष्ठ 1 का शेषांश...

कानून 'ढाल' बने ...

आया। उपलब्ध सीसीटीवी में प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला उन्हें परीक्षा-कक्ष से बाहर ले जाते दिखाई देते हैं। संस्थान के अनुसार प्रश्नपत्र को चैटजीपीटी पर डालकर उत्तर पाने की कोशिश की गई थी। उसी दिन साहिल की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके पिता ने जातिगत भेदभाव और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी-एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया तथा जांच अपराध शाखा को सौंप दी।

लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि परिवार के आरोप अभी आरोप हैं, न्यायिक निष्कर्ष नहीं। आईआईटी बॉम्बे ने जातिगत भेदभाव के आरोपों से इनकार किया है। संस्थान का कहना है कि साहिल ने प्रशासन या एससी-एसटी प्रकोष्ठ में ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। दूसरी ओर परिवार अपने आरोपों पर कायम है और साहिल के माता-पिता ने कार्रवाई की मांग को लेकर मुंबई में भूख हड़ताल शुरू की है।

तो सवाल है-क्या एफआईआर ही फैसला है?

नहीं। एफआईआर जांच का आरंभ है, अंत नहीं। आरोप अपराध-सिद्धि नहीं। सीसीटीवी परीक्षा-कक्ष की घटना दिखा सकता है, लेकिन वह यह तय नहीं करता कि साहिल की आत्महत्या के पीछे अंतिम कारण क्या था। यह जांच का विषय है।

यहीं एससी-एसटी कानून की प्रक्रिया पर गंभीर बहस जरूरी हो जाती है। कानून कठोर है, लेकिन क्या जांच भी उतनी ही निष्पक्ष, वैज्ञानिक और समयबद्ध है? किसी पर मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को जो क्षति होती है, उसका क्या? और यदि आरोप टिकते नहीं, तो क्या झूठे या दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने वाले के लिए पर्याप्त जवाबदेही है?

दूसरी तरफ यह सवाल भी उतना ही कठोर है- अगर कानून के दुरुपयोग की चर्चा के डर से वास्तविक पीड़ित की शिकायत को ही संदेह की नजर से देखा जाने लगे तो? तब कानून की ढाल कमजोर पड़ जाएगी और उसका सबसे बड़ा नुकसान उसी वर्ग को होगा, जिसके लिए वह बनाया गया है।

राशिफल

25 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2026 ।। विक्रम संवत 2083-**मास** : भाद्रपद, **पक्ष** : शुक्ल, **तिथि** :चतुर्दशी

मेष : सप्ताह की शुरुआत उत्साह और आत्मविश्वास के साथ होगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पुराने काम पूरे करने का अवसर मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें।

वृषभ : रुके हुए कामों में गति आएगी। नौकरी और व्यवसाय में मेहनत का परिणाम मिल सकता है। धन संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करें और निवेश से पहले पूरी जानकारी लें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

मिथुन : नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी बात को महत्व मिलेगा। आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। मित्रों से मुलाकात मन प्रसन्न करेगी।

कर्क : इस सप्ताह भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी को लेकर विचार कर सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा। धन की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन अचानक खर्च सामने आ सकता है।

सिंह : कार्यक्षेत्र में पहचान बढ़ सकती है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर मिलेंगे। घर-परिवार में सुखद वातावरण रहेगा।

कन्या : आपकी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन परिणाम भी सकारात्मक मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें।

तुला : सप्ताह आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। नौकरी या कारोबार में कोई नया अवसर सामने आए तो उसके सभी पक्षों को समझकर निर्णय लें।

वृश्चिक : कार्यक्षेत्र में नए ग्राहक या नए संपर्क बनने के संकेत हैं। पुराने अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है, लेकिन जोखिम वाले निवेश से बचना बेहतर रहेगा।

धनु : इस सप्ताह मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी। व्यापार में लाभ के अवसर आएंगे, लेकिन बड़े आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें। यात्रा संभव है।

मकर : आर्थिक मामलों में सावधानी के साथ आगे बढ़ें। सप्ताह के मध्य में कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।

कुंभ : रुका हुआ धन मिलने या आय का नया स्रोत बनने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में खर्च बढ़ सकता है।

मीन : सप्ताह की शुरुआत में कामकाज से जुड़े अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में लाभ की संभावना है।

सप्ताह के पर्व/त्योहार

25 सितंबर (शुक्रवार) : अनंत चतुर्दशी व्रत
26 सितंबर (शनिवार) : उमा माहेश्वर व्रत
27 सितंबर (रविवार) : महालया प्रारंभ, प्रतिप्रदा श्राद्ध
28 सितंबर (सोमवार) : द्वितीया श्राद्ध
29 सितंबर (मंगलवार) : तृतीया श्राद्ध
30 सितंबर (बुधवार) : चतुर्थी श्राद्ध

●ज्योतिर्विद् आचार्य अखिलेश्वर शुक्ल
भाग्योदय : पहला तल्ला, सेंट्रल प्लाजा, एमएस रोड
फैंसी बाजार, गुवाहाटी-781001 मो.-94350 40387

धन दिशा



जेब पर भारी न पड़े त्योहार की खुशी

मां दुर्गा का आगमन हो रहा है। महालया से लेकर दशमी तक नए कपड़े, पांडाल, मेला, खाना, परिवार। यह वक्त है जश्न का। और इस जश्न में कोमल जैन आपको रोकने नहीं आई हैं। लेकिन एक छोटी सी बात जरूर कहनी है, इस खुशी को अगले तीन महीने की तंगी में न बदलने दें।

हर साल अक्टूबर-नवंबर में देश भर में क्रेडिट कार्ड का खर्च एक नए रिकॉर्ड पर पहुंचता है और दिसंबर में लाखों परिवार उस बिल से जूझते हैं। त्योहार की खुशी तब खट्टी हो जाती है।

सबसे बड़ा जाल 'नो-कॉस्ट ईएमआई': दुकानदार कहता है 'कोई ब्याज नहीं।' लेकिन असलियत यह है कि नो-कॉस्ट ईएमआई में अक्सर प्रोसेसिंग फीस छुपी होती है, और अगर एक भी किस्त चूक गई तो ब्याज दर 36 प्रतिशत से 42 प्रतिशत सालाना तक पहुंच सकती है। यह कोई छोटी रकम नहीं है।

क्रेडिट कार्ड का 'मिनिमम ड्यू' : बिल आने पर सिर्फ मिनिमम ड्यू भरना सबसे महंगी आदत है। मान लीजिए 50,000 रुपए का बिल है और आप 2,500 रुपए भरते हैं -बाकी पर 36-42 प्रतिशत सालाना ब्याज लगता रहेगा। यह चक्र महीनों तक चलता है। हमेशा पूरा बिल चुकाएं।

एक 'पूजा बजट' बनाएं : त्योहार से पहले बैठकर तय करें — कपड़े, मिठाई, उपहार, यात्रा — कितना खर्च होगा। बस उतना ही खर्च करें। जो नकद में या यूपीआई से दे सकते हैं, वही खरीदें। क्रेडिट कार्ड से खरीदा है तो बिल आते ही पूरा चुकाएं।

इमरजेंसी फंड को हाथ न लगाएं : त्योहार की खरीदारी के लिए इमरजेंसी फंड तोड़ना सबसे बड़ी गलती है। हमने अंक 5 में यह बात की थी, वह फंड सिर्फ असली मुसीबत के लिए है। नए कपड़े उसमें नहीं आते।

मां दुर्गा की पूजा दिल से करें। पांडाल घूमें। परिवार के साथ खाएं। बस इतना याद रखें, त्योहार की असली खुशी वह होती है जो अगले महीने के बिल से डरकर नहीं आती। खुशी मनाएं समझदारी से।

अगले हफ्ते : नॉमिनी काफी नहीं, वसीयत क्यों जरूरी है? वह बात जो ज्यादातर परिवार नहीं जानते।

इस कॉलम के लिए आपका कोई सवाल है? हमें भेजिए

-कोमल जैन

पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट, संस्थापक, वेल्थप्लायर्स- मो. 9004510577

भांगागढ़ की मस्जिद गली की जमीन पर बड़ा खुलासा

सरकारी रिकॉर्ड में सड़क दर्ज

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

दिसपुर राजस्व चक्रधिकारी की रिपोर्ट गौहाटी हाईकोर्ट में पेश दाग संख्या 2675 की जमीन को बताया सरकारी भूमि

भांगागढ़ स्थित मस्जिद गली की जमीन को लेकर चल रहे न्यायिक विवाद में दिसपुर राजस्व चक्र कार्यालय की रिपोर्ट सामने आई है। 18 जून 2026 को जारी रिपोर्ट में डिसपुर राजस्व चक्र अधिकारी ने गौहाटी हाईकोर्ट को बताया है कि उपलब्ध भू-अभिलेख और भूमि राजस्व सहायक (एलआरए) की रिपोर्ट के अनुसार बेतोला मौजा के दाग संख्या 2675 के अंतर्गत आने वाली जमीन सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है और अभिलेख के टिप्पणी कॉलम में इसे सड़क के रूप में दर्ज किया गया है।

रिपोर्ट आई.ए. (सिविल) 1817/2026 मामले के संदर्भ में तैयार की गई है। इसमें बताया गया है कि हाईकोर्ट के 8 जून 2026 के आदेश के अनुपालन में मस्जिद गली की भूमि से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। राजस्व कार्यालय ने इसके साथ संबंधित चिट्ठा, ट्रेस मैप और जियो-टैग तस्वीरें भी संलग्न की हैं।

दस्तावेज में संलग्न तस्वीरों में भांगागढ़ क्षेत्र की सड़क के किनारे स्थित भू-भाग को चिह्नित किया गया है। तस्वीर पर गुवाहाटी के जीएस रोड, भांगागढ़ क्षेत्र का स्थान विवरण भी दर्ज है। इससे यह मामला केवल जमीन के स्वामित्व तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमि के वास्तविक उपयोग और स्थिति को लेकर भी महत्वपूर्ण सवाल सामने आते हैं।

राजस्व कार्यालय की रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है, जब संबंधित भूमि को लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन है। रिपोर्ट में उपलब्ध सरकारी अभिलेखों के आधार पर भूमि की स्थिति स्पष्ट की गई है। अब इस रिपोर्ट और संलग्न दस्तावेजों के आधार पर आगे की न्यायिक कार्यवाही में भूमि के रिकॉर्ड और उसके उपयोग से जुड़े पहलुओं पर विचार किया जा सकता है।

सरकारी रिकॉर्ड में दाग संख्या 2675 की भूमि को सरकारी जमीन और सड़क के रूप में दर्ज किए जाने की बात रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कही गई है। हालांकि, भूमि पर अंतिम कानूनी अधिकार अथवा विवाद का न्यायिक निष्कर्ष अदालत की कार्यवाही पर निर्भर करेगा।

सीईसी के खिलाफ प्रदर्शन, गौरव गोगोई हिरासत में

गुवाहाटी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद गौरव गोगोई समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने यह प्रदर्शन विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मतदाता सूची में बदलावों को लेकर किया था। पार्टी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने और मामले की स्वतंत्र समीक्षा की मांग की। कांग्रेस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। वहीं, पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक प्रदर्शन पर कार्रवाई बताया है।

भाजपा उम्मीदवारों के प्रमाणपत्रों पर कांग्रेस का सवाल

सुरजीत चक्रवर्ती

सिलचर। सिलचर नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भाजपा के 13 उम्मीदवारों के नामांकन दस्तावेजों पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सिलचर जिला कांग्रेस का आरोप है कि इन उम्मीदवारों ने नामांकन के साथ संदिग्ध प्रमाणपत्र जमा किए हैं। हालांकि, प्रमाणपत्र फर्जी हैं या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है और अंतिम स्थिति चुनाव आयोग की जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता अमित कालर ने इस मुद्दे पर भाजपा से सवाल उठाए। वहीं, कांग्रेस नेता पापन देव ने भाजपा नेत्री सुष्मिता देव पर भी आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि कुछ कांग्रेस उम्मीदवारों पर दबाव डालकर नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग से जांच कर लोकतांत्रिक माहौल सुनिश्चित करने की मांग की।

सिलचर : भाजपा का 'संकल्प पत्र', शहरी विकास पर दिया जोर

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी



सिलचर नगर निगम के आगामी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना 'नगर क्षेत्र विकास संकल्प पत्र' जारी किया। वित्त एवं वन मंत्री जयंत मल्ल बरुवा की मौजूदगी में जारी किए गए इस दस्तावेज में सिलचर को आधुनिक, सुव्यवस्थित और प्रगतिशील शहर के रूप में विकसित करने की पार्टी की प्राथमिकताओं को सामने रखा गया है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया, विधायक कौशिक राय समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

भाजपा के संकल्प पत्र में मुख्य जोर शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर दिया गया है। पार्टी ने शहर के विकास को अपनी चुनावी मुहिम के प्रमुख केंद्र में रखा है। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट में संकल्प पत्र की सभी योजनाओं और उनके वित्तीय प्रावधानों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। सिलचर नगर निगम का यह पहला चुनाव है। नवगठित निगम में कुल 42 वार्ड हैं। नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दो भाजपा उम्मीदवार (वार्ड 9 से बिजेंद्र प्रसाद सिंह और वार्ड 20 से भक्ति सेन तालुकदार) निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। अब शेष 40 वार्डों में 3 अक्टूबर को मतदान होना है। मतगणना 6 अक्टूबर को प्रस्तावित है। भाजपा ने 38 वार्डों में उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि उसकी सहयोगी असम गण परिषद (एजीपी) चार वार्डों में चुनाव लड़ रही है। इस तरह गठबंधन ने सभी 42 वार्डों में उम्मीदवार खड़े किए हैं।

सिलचर के पहले नगर निगम चुनाव में शहरी प्रशासन, सड़क और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे चुनावी विमर्श के केंद्र में हैं। भाजपा का नया संकल्प पत्र इसी विकास एजेंडे को मतदाताओं के सामने रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

संपादकीय

हाउस हसबैंड क्यों नहीं

मद्रास हाई कोर्ट की हालिया टिप्पणी केवल एक वैवाहिक विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि बदलते भारतीय समाज के सामने एक जरूरी सवाल रखती है-जब घर संभालने वाली महिला को 'गृहिणी' कहा जा सकता है, तो घर और परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाले पुरुष को 'गृहपति' या 'हाउस हसबैंड' कहने में संकोच क्यों? अदालत ने साफ कहा कि 'होममेकर' किसी एक लिंग तक सीमित शब्द नहीं है और घरेलू जिम्मेदारियों को निभाने वाले व्यक्ति के श्रम का आर्थिक मूल्य है।

यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय परिवारों में लंबे समय से कमाई को ही आर्थिक योगदान और घरेलू काम को केवल पारिवारिक कर्तव्य मानने की प्रवृत्ति रही है। खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, घर की व्यवस्था संभालना और परिवार के दूसरे सदस्य को अपने पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने का अवसर देना-ये सभी ऐसे काम हैं जिनका बाजार में सीधा मूल्य भले न दिखाई दे, लेकिन परिवार की अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

मदुरै पीठ के सामने आए डॉक्टर दंपति के मामले में भी यही पहलू सामने आया। पत्नी ने पति की उच्च चिकित्सा शिक्षा के दौरान परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी संभाली। बाद में वैवाहिक संबंधों में गंभीर मतभेद उत्पन्न हुए और दोनों अलग रहने लगे। अंततः आपसी सहमति से तलाक हुआ तथा पति ने पत्नी और दोनों बच्चों के लिए कुल 2.5 करोड़ रुपए देने पर सहमति जताई।

अदालत की टिप्पणी का असली महत्व 'हाउस हसबैंड' शब्द में नहीं, बल्कि उस सोच में है जो इसके पीछे है। परिवार साझेदारी है, पदानुक्रम नहीं। कमाने वाले और घर संभालने वाले-दोनों की भूमिका जरूरी है। यदि पुरुष घर संभालता है तो उसका सम्मान कम नहीं होना चाहिए और यदि महिला परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाती है तो उसकी घरेलू भूमिका भी कमतर नहीं आंकी जानी चाहिए।

आम और खास में अंतर

जन जन विचार

...✍ नीरज कुमार दुबे

नई दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चल रही कवायद के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरी प्रक्रिया पर फिर से बहस तेज कर दी है। हम आपको बता दें कि जिन प्रमुख और चर्चित मतदाताओं के नाम पर एसआईआर के दौरान नोटिस जारी हुए थे, उनमें से अधिकांश के विवरण और दस्तावेजों का सत्यापन अब पूरा कर लिया गया है और उन्हें अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाने के लिए हरी झंडी मिल गई है। इनमें पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे चर्चित नाम शामिल हैं।

इसके अलावा विदेश सचिव विक्रम मिस्री, पूर्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे अरविंद पनगढ़िया, भाजपा विधायक कैलाश गहलोत, पूर्व सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग सहित कई अन्य प्रमुख लोगों को भी एसआईआर के दौरान नोटिस मिला था। चुनाव अधिकारियों के अनुसार इन मामलों की व्यक्तिगत रूप से जांच की गई और संबंधित मतदाताओं से आवश्यक जानकारी तथा दस्तावेज हासिल किए गए। सत्यापन पूरा होने के बाद इनके नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।

दरअसल, इन चर्चित नामों को नोटिस मिलने के बाद सवाल उठने लगे थे कि आखिर ऐसे लोगों के नाम भी एसआईआर की जांच के दायरे में कैसे आ गए? चुनाव अधिकारियों का कहना है कि मतदाता विवरण में कुछ तार्किक विसंगतियां मिली थीं या फिर मौजूदा विवरण पिछली गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़े अभिलेखों से मेल नहीं खा रहा था। इसी आधार पर संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए। अधिकारियों के मुताबिक नोटिस मिलना अपने आप में मतदाता सूची से नाम काटे जाने का संकेत नहीं है, बल्कि यह संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने का अवसर देता है।

लेकिन असली सवाल यहीं से पैदा होता है। दिल्ली में एसआईआर के तहत करीब 33 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने की बात सामने आई है। यानी यह प्रक्रिया केवल कुछ चर्चित चेहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर लाखों आम मतदाताओं पर पड़ रहा है। नोटिस जारी होने के बाद आम मतदाता को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी पात्रता और विवरण साबित करने के लिए दस्तावेज जुटाने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ चर्चित और प्रभावशाली लोगों के मामलों में अधिकारियों द्वारा संपर्क कर दस्तावेज जुटाने और सत्यापन पूरा करने की प्रक्रिया सामने आई है।

यही अंतर अब एसआईआर की पूरी कवायद के केंद्र में आ गया है। कुछ रिपोर्टों में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के एसआईआर में अधिकारियों के स्तर पर वीआईपी मतदाताओं की पहचान कर उनके सत्यापन के लिए अलग तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इन रिपोर्टों के अनुसार सामान्य मतदाताओं को जहां नोटिस के बाद सुनवाई और दस्तावेजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, वहीं प्रभावशाली मतदाताओं के मामलों में प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान रही। यह आरोप चुनावी प्रक्रिया की समानता और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।

हालांकि चुनाव अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष यह है कि नोटिस जारी करने का आधार मतदाता के पद या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि एसआईआर के दौरान सामने आई विसंगतियां हैं और सभी मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि अंतिम मतदाता सूची चार नवंबर को प्रकाशित की जानी है, जबकि नोटिसों के निस्तारण की प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक पूरी की जानी है।

इस पूरे घटनाक्रम में फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि जिन चर्चित मतदाताओं के नाम एसआईआर के दौरान सवालों के घेरे में आए, वे सत्यापन के बाद अंतिम सूची में जगह पाने की स्थिति में हैं। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि लाखों आम मतदाताओं के मामलों का निस्तारण किस गति और किस समान प्रक्रिया के तहत होता है और चार नवंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची एसआईआर को लेकर उठे सवालों का कितना स्पष्ट जवाब देती है। बहरहाल, इतना तो दिख ही रहा है कि चुनाव आयोग की ओर से आम और खास में फर्क किया जा रहा है।

नैतिक पतन की पराकाष्ठा

जन जन विचार

...✍ डॉ. अनूप मिश्रा

राजनीतिक बहसों में मतभेद और तीखे हमले भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा रहे हैं, लेकिन जब विरोध का माध्यम व्यक्तिगत आक्षेप और किसी की गरिमा व धार्मिक आस्था को आहत करने वाले फर्जी आधुनिक साधनों तक पहुंच जाए, तो यह गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से निर्मित एक वीडियो प्रस्तुत करने का मामला इसी विषय को रेखांकित करता है। डीपफेक और एआई की मदद से किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति अथवा किसी धार्मिक पीठ के प्रमुख का विकृत रूप पेश करना केवल एक राजनीतिक विरोधी पर प्रहार भर नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक जीवन में शुचिता, सामान्य शिष्टाचार और नैतिक सीमाओं के पतन को भी दर्शाता है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक चुने हुए जन-प्रतिनिधि और संवैधानिक प्रमुख होने के साथ-साथ लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र 'गोरक्षपीठ' के पीठाधीश्वर भी हैं। भारत की संत परंपरा और श्रद्धालुओं के मन में इस पीठ का विशेष और पूजनीय स्थान है। राजनीतिक विरोध की अपनी सीमाएं होती हैं। नीतियों, कानून-व्यवस्था, विकास और भ्रष्टाचार पर सवाल पूछना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है। किंतु, एआई तकनीक के जरिए किसी पीठाधीश्वर के चरित्र और आस्था से जुड़ी झूठी तस्वीरें गढ़ना सार्वजनिक विमर्श के गिरते स्तर का, पतन का प्रतीक है।

सपा कार्यालय में घटित इस घृणित कार्य का सबसे विरोधाभासी पहलू यह है कि इसमें ऐसे व्यक्ति पर कीचड़ उछालने का प्रयास किया गया, जिसका व्यक्तिगत व सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब की तरह और निष्कलंक रहा है। आप उनसे धार्मिक या राजनीतिक मतभेद रख सकते हैं। लेकिन वह चाहें गोरक्षपीठाधीश्वर की भूमिका में सामने आएं अथवा सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में, आप योगी आदित्यनाथ पर कदाचार या विलासी जीवन जीने का आरोप नहीं लगा सकते। वह एक कॉरपोरेट सीईओ की कार्यशैली में पूरी कुशलता से प्रदेश का संचालन करते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली एक संत या संन्यासी जैसी ही रहती है। राम मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह स्वतंत्र ट्रस्ट के अधीन है, लेकिन ट्रस्ट का अनुरोध पत्र मिलते ही उन्होंने चढ़ावा प्रकरण पर एसआईटी का गठन कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इसके बावजूद अगर कोई योगी आदित्यनाथ को इस प्रकरण से जोड़ने का भोंडा प्रयास करता दिखाई दे तो इसे चुनावी लाभ के लिए पतन की पराकाष्ठा ही कहा जा सकता है।

यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक हो जाता है कि गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में गुरु गोरखनाथ धाम का संपूर्ण नियंत्रण योगी आदित्यनाथ के पास है। पीठ को नाथ संप्रदाय के देश-दुनिया में बसे अनुयायियों व अन्य भक्तों से नियमित चढ़ावा प्राप्त होता होगा। साधारण गेरुआ वस्त्र पहनने, साधारण भोजन करने और साधारण बिस्तर पर सोने वाले योगी आदित्यनाथ आखिर क्या करते हैं इस धनराशि का? सपा प्रमुख ने इस बारे में एक क्षण भी सोचा होता तो वह ऐसा आरोप लगाने से पहले सौ बार सोचते। उन्हें मालूम होना चाहिए कि गुरु गोरखनाथ धाम प्रतिदिन हजारों लोगों का पेट भरने के अलावा विगत कई वर्षों से अनेक चैरिटेबल स्कूल-कॉलेज, विश्वविद्यालय, चिकित्सालयों का संचालन और समाज के वंचित तबकों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहा है।



ट्रेन में युवक की संदिग्ध मौत

जंदाहा/वैशाली। महिसौर थाना क्षेत्र के चांदसराय गांव निवासी करीब 21 वर्षीय नितिन कुमार की ट्रेन यात्रा के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। नितिन हैदराबाद से दानापुर लौट रहा था। आरा रेलवे स्टेशन से करीब 300-400 गज दूर रेलवे ट्रैक से उसका शव बरामद हुआ। परिजनों का आरोप है कि उसके हाथ-पैर कुर्ते से बंधे थे और ट्रेन की चपेट में आने से शव कई हिस्सों में बंट गया। परिजनों के अनुसार, 20 सितंबर की रात नितिन के मोबाइल से फोन आया था। फोन करने वाले ने सिगरेट पीने के आरोप में पुलिस द्वारा पकड़े जाने की बात कहते हुए 10 हजार रुपए की मांग की। बाद में परिजनों ने फोन-पे के जरिए 5 हजार रुपए भेजे, जिसके बाद कथित तौर पर 20 हजार रुपए की अतिरिक्त मांग की गई। 21 सितंबर को भी उसके मोबाइल से कभी-कभी फोन आने की बात परिजनों ने बताई। नितिन हैदराबाद में मजदूरी करता था और घर पर टेंट का काम भी करता था। दादा की तबीयत खराब होने की सूचना पर वह घर लौट रहा था। शव गांव पहुंचने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की परिस्थितियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

सरकारी राशि गबन मामले में चिकित्सक गिरफ्तार

शिवहर। पुरनहिया पीएचसी में सरकारी राशि के गबन व वित्तीय अनियमितता के मामले में पूर्व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. प्रेमकुंज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी शैलेंद्र सिंह के निर्देश पर पुरनहिया थाना पुलिस ने यह कार्रवाई प्राथमिकी के आधार पर की। डॉ. कुमार पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के झिटकहिया गांव के निवासी हैं। विभागीय जांच व विशेष ऑडिट में करीब 30 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता सामने आई थी। जांच में फर्जी बिलिंग, ममता प्रोत्साहन राशि में हेराफेरी और बिना स्वीकृति राशि निकासी के मामले पाए गए थे। मामले में डॉ. कुमार और तत्कालीन लिपिक राजीव रंजन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को निलंबित किया गया था। अनुसंधान में मिले साक्ष्यों के आधार पर डॉ. कुमार की गिरफ्तारी की गई है।

भवन निर्माण निगम के जीएम के चार ठिकानों पर छापेमारी

पटना। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक कमलेश कुमार के चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ईओयू के अनुसार, कमलेश कुमार के खिलाफ वैध आय से 103 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अवैध संपत्ति का अनुमान 3 करोड़ 12 लाख 51 हजार रुपए से अधिक बताया गया है। टीमों ने वैशाली के जंदाहा स्थित पैतृक घर, पटना के एसके पुरी स्थित मनमोहन अपार्टमेंट के फ्लैट, राजीव नगर की मेधा बिल्डिंग और भवन निर्माण निगम स्थित उनके कार्यालय कक्ष में तलाशी ली। कार्रवाई में दो दर्जन से अधिक अधिकारी व पुलिसकर्मी शामिल रहे।

अब मंदार पर्वत पर युवती से अभद्रता का वीडियो वायरल

जन जन विचार
...✍ बांका

सम्राट राज में बदमाश बेखौफ, महिलाएं सुरक्षित नहीं

बिहार में युवती से बदसलूकी के वीडियो सामने आने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। जमुई और समस्तीपुर के बाद अब बांका के प्रसिद्ध मंदार पर्वत से युवती के साथ कथित अभद्रता का पुराना वीडियो सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद बौंसी पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में तीन युवकों की पहचान की है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, घटना 3 जून 2026 की है, जबकि इसका वीडियो 22 सितंबर को बौंसी थाना के सामाजिक माध्यम प्रकोष्ठ को व्हाट्सऐप के जरिए मिला। वीडियो की जांच के बाद पुलिस टीम मंदार पर्वत पहुंची और घटनास्थल का सत्यापन किया। स्थानीय दुकानदारों और ग्रामीणों से पूछताछ के बाद मामले में बौंसी थाना कांड संख्या 248/26 दर्ज किया गया।

दो दोस्तों के साथ मंदार घूमने गई थी युवती

पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक युवती 3 जून को अपने दो दोस्तों के साथ मंदार पर्वत घूमने गई थी। इसी दौरान वीडियो में दिखाई दे रहे तीन युवकों ने कथित तौर पर उसे घेर लिया। पुलिस के अनुसार, युवती का हाथ पकड़कर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, गाली-गलौज की गई और धमकी भी दी गई।

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, आरोपियों में शामिल अब्दुल्ला ने युवती के दोस्त से ऑनलाइन माध्यम से अपने खाते में 1,500 रुपए भी मंगवाए। इसके बाद युवती और उसके साथियों को वहां से जाने दिया गया।

भूमिहीन परिवारों को मिलेगा वासभूमि का अधिकार

जन जन विचार
...✍ शिवहर

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा पात्र भूमिहीन परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'बसेरा अभियान' संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत जिले में पात्र भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर वासभूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

जिला प्रशासन, शिवहर द्वारा जिले के सभी पात्र भूमिहीन परिवारों से अपील की गई है कि वे अपने संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन जमा कर अभियान का लाभ उठाएं।

कौन कर सकता है आवेदन?

अभियान के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पात्र भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जाएगा।

आवेदन के साथ उपलब्ध कराएं आवश्यक विवरण

आवेदन करते समय परिवार के सभी सदस्यों का विवरण एवं मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। आवेदक को स्वयं के साथ-साथ पति/पत्नी एवं वयस्क पारिवारिक सदस्यों के आधार की स्व-अभिप्रमाणित प्रति भी आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिन पात्र परिवारों को पूर्व में किसी सरकारी योजना के माध्यम से वासभूमि प्राप्त नहीं हुई है, वे इस अभियान के तहत आवेदन कर सकते हैं।

शिकायत एवं सुझाव के लिए सुविधा

अभियान के तहत आवेदन अथवा वासभूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की समस्या, शिकायत या सुझाव होने पर बिहार भूमि एवं राजस्व विभाग के जन-शिकायत पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है।

वेबसाइट : biharbhumi.bihar.gov.in

जिला प्रशासन, शिवहर ने पात्र भूमिहीन परिवारों से अपील की है कि वे इस अभियान का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित अंचल कार्यालय में शीघ्र आवेदन करें तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन जमा करें।

सांसद लवली आनंद का विकास योजनाओं की गुणवत्ता व समयबद्धता पर बल

जन जन विचार
...✍ मधुबनी

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में सांसद लवली आनंद की अध्यक्षता में हुई। बैठक का शुभारंभ जिला पदाधिकारी प्रतिभा रानी, पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष एवं नगर सभापति राजन नंदन सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।



बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। सांसद ने अधिकारियों को सड़क, भवन एवं अन्य आधारभूत संरचना से जुड़े कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने तथा निर्माण की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं करने का निर्देश दिया।

उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सीवरेज, पेयजल, जल जीवन मिशन और ग्रामीण विकास योजनाओं की भी समीक्षा की। सांसद ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को समय रहते दूर किया जाए और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सभी विभागों की प्राथमिकता होनी चाहिए। दिशा में योजनाओं की नियमित निगरानी और पारदर्शी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया।

तस्वीर पर सियासत

जन जन विचार
...✍ पटना/जमुई

मुई में नाबालिग छात्रा के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना के बाद शुरू हुआ विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सोशल मीडिया खाते से पीड़िता और उसके परिजनों के साथ तस्वीर साझा किए जाने को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और सांसद मीसा भारती ने आरोप लगाया है कि तस्वीर से नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर होने का खतरा पैदा हुआ। दोनों ने मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, तस्वीर कुछ समय बाद सोशल मीडिया से हटा दी गई।

19 सितंबर की घटना से शुरू हुआ मामला

जमुई में 19 सितंबर की शाम कोचिंग से लौट रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की को कुछ युवकों ने रास्ते में रोक लिया था। आरोप है कि दोनों को घेरकर पूछताछ की गई और उनके साथ मारपीट तथा छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान के लिए वीडियो फुटेज को आधार बनाया। रिपोर्टों के अनुसार, तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है।



जांच के बीच मुख्यमंत्री से मिला परिवार

घटना के बाद पीड़िता अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिली। अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने परिवार को त्वरित न्याय का भरोसा दिया और कहा कि मामले की सुनवाई तेज गति से कराकर आरोपियों को एक महीने के भीतर कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसी मुलाकात की तस्वीर बाद में मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया खाते पर साझा की गई।

तस्वीर पर तेजस्वी का सवाल

तस्वीर सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर नाबालिग की पहचान उजागर करने का आरोप लगाया। उन्होंने बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के प्रावधानों का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि जब पुलिस सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली सामग्री को लेकर कार्रवाई कर रही है, तब मुख्यमंत्री के खाते से साझा तस्वीर पर भी सवाल उठना चाहिए।

राजद सांसद मीसा भारती ने भी तस्वीर का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए बिहार पुलिस से मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। उनका आरोप है कि नाबालिग पीड़िता की निजता की रक्षा की जानी चाहिए और पहचान उजागर करने वाली किसी भी सामग्री पर कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।

अब असली सवाल-पीड़िता की पहचान की सुरक्षा

जमुई की घटना ने पहले ही नाबालिगों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अब तस्वीर को लेकर पैदा हुआ विवाद पीड़िता की पहचान और निजता की सुरक्षा के मुद्दे को केंद्र में ले आया है। एक ओर सरकार की ओर से आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई और जल्द न्याय का भरोसा दिया गया है, वहीं विपक्ष मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है। तस्वीर हटाए जाने के बावजूद विवाद थमा नहीं है। अब निगाह पुलिस की कार्रवाई और इस आरोप पर आधिकारिक स्पष्टीकरण पर है।



'कानून से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं'

संजय गुप्ता, शिवहर। राष्ट्रीय जनता दल के नेता व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राधाकांत गुप्ता उर्फ बच्चू ने बताया है कि जमुई में नाबालिग के साथ छेड़खानी मामले में पुलिस के द्वारा मुख्य आरोपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। जो काफी सराहनीय है। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बच्चू ने बताया है कि जमुई की शर्मनाक घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपित समेत पांच लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस की तत्परता समाज को यह संदेश देने का प्रयास है कि किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। एक आरोपित के पैर में गोली भी मारी गई है, उसने पुलिस पर हमला करने का दुस्साहस किया था।

राजद नेता राधाकांत गुप्ता और बच्चू ने आम लोगों को भरोसा दिलाया है कि स्थानीय पुलिस द्वारा आरोपितों को तत्काल पकड़कर समाज को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं है। बच्चू ने कहा कि स्थानीय पुलिस ने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर छात्रा की पहचान उजागर करने वाले दोषियों पर भी लगाम कसकर बढ़िया काम किया गया है। आज हर हाथ में मोबाइल है, यूजर कुछ भी पोस्ट या शेयर करने से पहले सोच नहीं रहा। यह कार्रवाई शायद बिना सोचे समझे पोस्ट करने वालों को भी सबक सिखाएगा।

पंचायत-वार्ड स्तर पर लगेंगे 'सेवा सेतु शिविर'

मधुबनी। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले में 25 सितंबर से पंचायत एवं वार्ड स्तर पर 'सेवा सेतु शिविर : सरकार आपके द्वार' का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में आम लोगों से सरकारी योजनाओं, सेवाओं से जुड़े आवेदन, समस्याएं एवं शिकायतें प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन के लिए 6 से 8 अक्टूबर तक मिशन मोड अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी के निर्देश पर डीडीसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक कर माइक्रोप्लान तैयार करने और स्थलवार कर्मियों की तैनाती का निर्देश दिया। संबंधित विभागों को आवेदनों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया है। शिविरों की निगरानी के लिए वरीय पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों एवं भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासन ने शिविरों के व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने आमजनों से शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याएं एवं आवेदन दर्ज कराने की अपील की है।

स्कूलों का होगा कायाकल्प, बदलेगी मधुबनी की शिक्षा की तस्वीर

जन जन विचार
...✍ प्रणय कुमार, मधुबनी

मधुबनी में शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी तेज हो गई है। सरकारी विद्यालयों को केवल भवन और कक्षाओं तक सीमित रखने के बजाय उन्हें आधुनिक, डिजिटल, सुविधायुक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने की व्यापक कार्ययोजना पर काम शुरू किया गया है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की पहल पर चलाए जा रहे 'मिशन कायाकल्प मधुबनी' के तहत विद्यालयों की वास्तविक स्थिति और जरूरतों का आकलन कर उनके विकास की अलग-अलग योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

जिलाधिकारी ने प्राइवेट स्कूल एवं चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, मधुबनी के तत्वावधान में आयोजित शिक्षाविद सम्मान समारोह में कहा कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह बच्चों



के व्यक्तित्व, विचार, संस्कार, अनुशासन और भविष्य को आकार देने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने अभिभावकों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से शिक्षा के प्रति जागरूक होने तथा जिले में शिक्षा की अलख जगाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।

भवन से लेकर डिजिटल शिक्षा तक एक साथ होगा काम

'मिशन कायाकल्प मधुबनी' का दायरा केवल विद्यालयों की मरम्मत या भवन निर्माण तक सीमित नहीं रखा गया है। योजना के तहत आधारभूत संरचना, मूलभूत सुविधाएं, आधुनिक शिक्षण संसाधन और शिक्षा की गुणवत्ता-इन सभी क्षेत्रों पर एक साथ काम करने की योजना है।

जिलाधिकारी के अनुसार विद्यालयों को उनकी वर्तमान स्थिति और जरूरतों के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे विद्यालय हैं जो आधारभूत संरचना की दृष्टि से गंभीर स्थिति में हैं। ऐसे विद्यालयों में भवन निर्माण और आवश्यक संरचनाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।

दूसरी श्रेणी में उन विद्यालयों को रखा गया है जहां बच्चों के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इन स्कूलों में बैठने की व्यवस्था, पेयजल, पंखे, शौचालय सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।

तीसरी श्रेणी में ऐसे विद्यालयों को शामिल किया गया है जहां आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों का विस्तार किया जा सकता है। यहां स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन कक्षाएं और आधुनिक प्रयोगशालाएं विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बदलती तकनीकी दुनिया के अनुरूप शिक्षा उपलब्ध कराना है।

एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा

जन जन विचार
...✍ आइची-नागोया

एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार अभियान लगातार जारी है। निशानेबाजी में पदकों की बारिश के बाद अब एथलेटिक्स के मैदान से भी भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। भारत ने एथलेटिक्स में रजत और कांस्य पदकों की झड़ी लगाते हुए अपना दम दिखाया। सबसे ऐतिहासिक उपलब्धि महिला पोल वॉल्ट में बरानिका इलांगोवन ने हासिल की, जिन्होंने भारत को इस स्पर्धा में एशियाई खेलों का पहला पदक दिलाया।

बरानिका ने 4.15 मीटर की ऊंचाई पार कर कांस्य पदक अपने नाम किया। कजाखस्तान की पोलिना इवानोवा ने भी 4.15 मीटर का प्रयास सफल किया, जिसके बाद दोनों को संयुक्त रूप से कांस्य दिया गया। बरानिका की यह उपलब्धि भारतीय एथलेटिक्स के लिए इसलिए खास है क्योंकि एशियाई खेलों में पोल वॉल्ट में भारत इससे पहले पदक नहीं जीत सका था।

गुलवीर ने लंबी दौड़ में बढ़ाया मान

पुरुषों की 10 हजार मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने शानदार धैर्य और दमखम दिखाते हुए रजत पदक जीता। उन्होंने 28 मिनट 29.38 सेकेंड का समय निकाला। बहरीन के बिरहानु बालेव ने स्वर्ण जीता। गुलवीर का यह प्रदर्शन 2023 एशियाई खेलों में जीते कांस्य से एक कदम आगे है।

गुलवीर की सफलता इसलिए भी उल्लेखनीय है कि 10 हजार मीटर जैसी कठिन स्पर्धा में अंतिम चरण तक अपनी गति और संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती होती है। उन्होंने आखिरी दौर में मजबूती बरकरार रखी और भारत की पदक तालिका में एक और रजत जोड़ दिया।



बरानिका इलांगोवन ने महिला पोल वॉल्ट में भारत को एशियाई खेलों का पहला पदक दिलाया।

मनप्रीत ने गोला फेंक में दिलाया कांस्य

महिला गोला फेंक में मनप्रीत कौर ने 17.17 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ कांस्य पदक हासिल किया। उनके अंतिम प्रयास में मौका था, लेकिन वह फाउल हो गया। इसके बावजूद मनप्रीत ने पोडियम पर जगह बनाकर भारत के खाते में एक और एथलेटिक्स पदक जोड़ा।

एथलेटिक्स के मैदान पर इन सफलताओं ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय खेलों में पदकों का दायरा अब कुछ चुनिंदा स्पर्धाओं तक सीमित नहीं रहा। निशानेबाजी के बाद एथलीटों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बरानिका का ऐतिहासिक कांस्य इस अभियान की सबसे खास उपलब्धियों में शामिल हो गया है।

भारत के लिए संदेश साफ है- एशियाई खेलों में पदक की दौड़ अब केवल निशाने पर नहीं, ट्रैक और मैदान पर भी उतनी ही मजबूती से जारी है।



पृष्ठ 1 का शेषांश...

कटघरे में चुनाव आयोग

टीएन शेषन से लवासा तक विवादों का लंबा सिलसिला

निर्वाचन आयोग के इतिहास में विवाद नए नहीं हैं। टीएन शेषन के कार्यकाल में चुनाव सुधार और आयोग की शक्तियों को लेकर तीखी बहस हुई। 2002 में गुजरात विधानसभा चुनाव टालने के तत्कालीन आयोग के फैसले पर भी राजनीतिक विवाद हुआ। 2009 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी ने चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया।

2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के असहमति नोटों को सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की मांग भी चर्चा में रही। बाद में उन्होंने चुनाव आयोग से इस्तीफा दे दिया। इन घटनाओं ने यह सवाल उठाया कि बहु-सदस्यीय संवैधानिक संस्था के भीतर मतभेदों को किस तरह दर्ज और सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

सबसे अहम सवाल : नियुक्ति प्रक्रिया कितनी स्वतंत्र?

निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पर बहस केवल उसके फैसलों तक सीमित नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। 2023 के अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका के प्रभाव को लेकर उठाए गए सवालों पर विचार किया था। बाद में संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 बनाया। इस कानून में नियुक्ति के लिए चयन समिति की व्यवस्था की गई है। 2024 में इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं में विशेष रूप से इस बात पर सवाल उठाया गया कि चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में यह चुनौती दर्ज है।

'इनाम' की बहस भी उठती रही

निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पर बहस का एक दूसरा पहलू सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले पद हैं। इतिहास में कुछ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों को बाद में राज्यपाल, विधि आयोग या अन्य संवैधानिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारियां मिलीं। समर्थक इसे उनकी प्रशासनिक विशेषज्ञता का उपयोग मान सकते हैं, जबकि आलोचक ऐसे पदों को लेकर संभावित हित-संघर्ष और संस्थागत धारणा के सवाल उठाते रहे हैं।

यही वजह है कि चुनाव आयोग के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों को लेकर चर्चा केवल किसी एक चुनाव या एक अधिकारी तक सीमित नहीं रहती। मुद्दा व्यापक है- क्या चुनाव कराने वाली संस्था राजनीतिक सत्ता से पर्याप्त दूरी बनाए रखते हुए अपने संवैधानिक दायित्व निभा रही है और क्या उसकी कार्यप्रणाली जनता के भरोसे के अनुरूप पारदर्शी है?

लोकतंत्र में भरोसा सबसे बड़ी कसौटी

निर्वाचन आयोग के पास मतदाता सूची, चुनाव कार्यक्रम, आचार संहिता और चुनाव संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकार हैं। इसलिए आयोग के हर बड़े निर्णय का असर सीधे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ता है। मौजूदा विवादों में राजनीतिक दलों के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष संबंधित न्यायिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं से ही निकलेंगे।

ताजा याचिकाओं पर अदालत की सुनवाई, एसआईआर से जुड़े विवाद और आयोग की निर्णय प्रक्रिया आने वाले दिनों में इस बहस को और स्पष्ट कर सकते हैं। सवाल किसी एक व्यक्ति या सरकार का नहीं, बल्कि उस संवैधानिक संस्था पर जनता के भरोसे का है, जिसके हाथ में देश के चुनावों की निष्पक्षता की जिम्मेदारी है।

'वोट की चोरी नहीं चलेगी...

और एसआईआर को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर लगातार राजनीतिक और सार्वजनिक अभियान भी चलाया जा रहा है।

कृष्ण कांत झा 'गुड्डू' ने कहा कि एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े निर्णयों को लेकर निर्वाचन आयोग के भीतर कथित तौर पर सामने आए मतभेदों ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली को लेकर उठ रहे सवालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए।

पितृपक्ष : स्मृतियों, संस्कारों और कृतज्ञता का पखवाड़ा

जन जन विचार
...✍ अध्यात्म डेस्क

पूर्वज चले जाते हैं, विरासत नहीं

मनुष्य इस संसार से चला जाता है, लेकिन उसके कर्म, संस्कार और स्मृतियां पीछे रह जाती हैं। यही उसकी वास्तविक विरासत है। पितृपक्ष हमें इसी विरासत को पहचानने और आगे बढ़ाने का अवसर देता है।

आज जब आधुनिक जीवन हमें अपनी जड़ों से लगातार दूर कर रहा है, तब पितृपक्ष एक सांस्कृतिक स्मरण-पत्र की तरह सामने आता है। यह कहता है कि विकास की दौड़ में आगे बढ़िए, लेकिन पीछे छूटे उन हाथों को मत भूलिए जिन्होंने आपको चलना सिखाया।

पितृपक्ष अंतत: मृत्यु का नहीं, स्मृति का पर्व है; शोक का नहीं, कृतज्ञता का अवसर है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान केवल हमारे नाम से नहीं, बल्कि उन पीढ़ियों से भी बनती है जिनकी विरासत लेकर हम आज यहां खड़े हैं।

पूर्वजों के प्रति सबसे सच्ची श्रद्धांजलि शायद यही है कि हम ऐसा जीवन जिएं, जिसे देखकर आने वाली पीढ़ी भी अपने पूर्वजों को सम्मान से याद कर सके।

भारतीय संस्कृति में कुछ परंपराएं ऐसी हैं, जिनका अर्थ केवल पूजा-पाठ और कर्मकांड तक सीमित नहीं है। पितृपक्ष भी ऐसी ही परंपरा है। यह वह समय है जब मनुष्य अपने पूर्वजों को स्मरण करता है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है और यह स्वीकार करता है कि आज उसका अस्तित्व केवल उसके अपने प्रयासों का परिणाम नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों की विरासत है जिन्होंने उससे पहले जीवन जिया और परिवार, समाज तथा संस्कारों की नींव रखी।

भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक चलने वाले इस पक्ष में लोग अपने दिवंगत माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी और अन्य पूर्वजों का स्मरण करते हैं। परंपरा के अनुसार तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म किए जाते हैं। इन विधियों के पीछे मूल भावना श्रद्धा और कृतज्ञता की है।

श्राद्ध का अर्थ केवल कर्मकांड नहीं

'श्राद्ध' शब्द की जड़ 'श्रद्धा' में मानी जाती है। अर्थात किसी कर्म का मूल आधार विश्वास से अधिक सम्मान और कृतज्ञता है। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं, जिनके त्याग और संघर्ष ने हमारे वर्तमान को संभव बनाया। पितृपक्ष हमें रुककर पीछे देखने का अवसर देता है।

आज की पीढ़ी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन-रात मेहनत करती है। यही काम कभी हमारे माता-पिता और उनसे पहले की पीढ़ियों ने किया था। किसी ने खेत में पसीना बहाया, किसी ने परिवार चलाने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना किया,



किसी ने अपनी इच्छाएं त्यागकर बच्चों को पढ़ाया। उनके संघर्षों की पूरी कहानी शायद हमारे पास न हो, लेकिन हमारा वर्तमान उन संघर्षों की एक कड़ी जरूर है।

इसलिए पितृपक्ष का संदेश केवल इतना नहीं कि पूर्वजों के नाम पर कोई विधि पूरी कर दी जाए। इसका बड़ा संदेश है-अपनी जड़ों को मत भूलिए।

बदलते समय में परंपरा का नया अर्थ

आज परिवार छोटे हो रहे हैं। संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। बच्चे शिक्षा और रोजगार के लिए दूसरे शहरों या देशों में चले जाते हैं। ऐसे समय में पितृपक्ष का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि यह परिवार की स्मृति को जीवित रखने का अवसर देता है।

पूर्वजों को याद करना केवल उनके नाम लेने तक सीमित नहीं होना चाहिए। उनके जीवन से जुड़ी कहानियां अगली पीढ़ी को बताना भी उतना ही जरूरी है। बच्चों को यह जानना चाहिए कि उनके दादा ने कैसी परिस्थितियों में जीवन बिताया, उनकी दादी ने परिवार के लिए क्या त्याग किए और उनके पूर्वजों ने किन संघर्षों से परिवार को आगे बढ़ाया। यही स्मृतियां परिवार की वास्तविक विरासत होती हैं।

श्रद्धा के साथ सेवा भी

पितृपक्ष हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है-जीवन में रहते हुए माता-पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना। किसी दिवंगत व्यक्ति के नाम पर बड़े आयोजन करने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हमारे बीच मौजूद बुजुर्ग अकेलेपन और उपेक्षा का जीवन न जिएं। यदि पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो उनके मूल्यों को अपने जीवन में उतारना होगा। जरूरतमंद को भोजन कराना, किसी गरीब की सहायता करना, पशु-पक्षियों के लिए अन्न-पानी रखना, बुजुर्गों की सेवा करना और परिवार में प्रेम बनाए रखना-इन कार्यों में भी पितृस्मरण की भावना दिखाई दे सकती है।

श्राद्ध के बाद क्यों बरतते हैं संयम?

पितृपक्ष भारतीय परंपरा में ऐसा अवसर है, जब परिवार अपनी पिछली पीढ़ियों को याद करता है। माता-पिता, दादा-दादी और उन सभी पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है, जिनकी मेहनत, त्याग और संस्कारों से परिवार की अगली पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान इसी स्मरण और कृतज्ञता की परंपरा का हिस्सा माने जाते हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध कर्म पूरा होने के बाद भी व्यक्ति को कुछ समय तक संयम और सात्विकता बनाए रखनी चाहिए। इसके पीछे अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों की अपनी परंपराएं हैं। इन्हें वैज्ञानिक नियम या अनिवार्य व्यवस्था के बजाय धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपरा के रूप में समझना अधिक उचित है।

पहले अर्पण, फिर भोजन की परंपरा

श्राद्ध के बाद तुरंत भोजन न करने की परंपरा कई परिवारों में देखने को मिलती है। मान्यता है कि श्राद्ध में तैयार भोजन पहले ब्राह्मण भोजन और पंचबलि के माध्यम से समर्पित किया जाए। पंचबलि में गाय, कुत्ते, कौए, देवताओं और चींटियों के लिए भोजन का अंश निकालने की परंपरा बताई जाती है।

इसके पीछे एक व्यापक भाव यह है कि भोजन केवल मनुष्य के लिए नहीं है। प्रकृति और दूसरे जीवों के साथ भी हमारा संबंध है। इसलिए अपने भोजन का एक हिस्सा दूसरे जीवों के लिए निकालना साझेदारी और जीव-दया का प्रतीक माना जा सकता है।

सात्विक भोजन और संयम पर जोर

पितृपक्ष के दौरान सात्विक भोजन करने की परंपरा रही है। कई परिवार इस अवधि में मांसाहार, मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों से दूरी रखते हैं। कुछ परंपराओं में प्याज और लहसुन को भी इस अवधि में नहीं खाने की बात कही जाती है। यहां भी क्षेत्र और परिवार के अनुसार नियम अलग-अलग हो सकते हैं। मूल भावना यही है कि पितरों के स्मरण के दौरान जीवनशैली में सादगी, संयम और अनुशासन रखा जाए।

घर में शांति भी है पितृ-स्मरण का हिस्सा

पितृपक्ष को केवल पूजा और तर्पण तक सीमित नहीं किया गया है। परंपराओं में इस दौरान क्रोध, झगड़े, अपशब्द और बुजुर्गों के अपमान से बचने की सलाह दी जाती है।

आखिर पूर्वजों को याद करने का अर्थ उनके दिए संस्कारों को भी याद करना है। यदि घर में ही बुजुर्ग उपेक्षित हों, परिवार के सदस्य एक-दूसरे से कटु व्यवहार करें और जरूरतमंद की मदद करने से मुंह मोड़ा जाए, तो केवल कर्मकांड करने का उद्देश्य अधूरा रह जाता है।

इसलिए पितृपक्ष में गरीबों को भोजन कराना, पशु-पक्षियों के लिए अन्न-पानी रखना और बुजुर्गों की सेवा करना भी श्रद्धा की भावना से जोड़ा जाता है।

बाल-दाढ़ी और नई शुरुआत को लेकर भी मान्यता

कई पारंपरिक परिवारों में श्राद्ध के दिन बाल, नाखून या दाढ़ी कटवाने से बचने की परंपरा है। इसी तरह नए कपड़े, वाहन, संपत्ति जैसी मांगलिक खरीदारी या नए शुभ कार्यों की शुरुआत को भी कुछ लोग इस अवधि में टालते हैं।

हालांकि, यह नियम सभी समुदायों या परिवारों में समान नहीं है। बदलते समय में लोग अपनी पारिवारिक परंपरा, धार्मिक विश्वास और व्यक्तिगत सुविधा के अनुसार इनका पालन करते हैं।

असल संदेश कर्मकांड से कहीं बड़ा

पितृपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण सीख शायद यही है कि मनुष्य अपनी जड़ों को न भूले। पूर्वज केवल तस्वीरों में मौजूद चेहरे नहीं, बल्कि परिवार की स्मृतियों, संस्कारों और संघर्षों का हिस्सा हैं।

श्राद्ध के बाद कुछ घंटे या एक दिन संयम रखने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम पूरे वर्ष अपने माता-पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। किसी जरूरतमंद की सहायता करें, प्रकृति और जीव-जंतुओं के प्रति संवेदनशील रहें और परिवार में प्रेम बनाए रखें।

पितृपक्ष हमें अतीत में लौटने के लिए नहीं, बल्कि अपनी विरासत को समझकर बेहतर वर्तमान बनाने के लिए प्रेरित करता है। श्राद्ध की थाली में रखा एक अन्नकण, तर्पण में अर्पित जल और पूर्वजों की स्मृति-इन सबके पीछे आखिर एक ही भावना है- जिसने हमें जीवन दिया, उसकी विरासत के प्रति कृतज्ञ रहना।

ৰাইজৰ কথা ৰাইজৰ মাজলৈ
সাপ্তাহিক
জন জন বিচাৰ
৯
Guwahati, 25 September, 2026 Friday :: শুক্রবাৰ, ভাদ, শুক্ল পক্ষ, চতুৰ্দশী, শকাব্দ ১৯৪৮

ব্রহ্মপুত্র-চাও ফ্রায়া সংলাপ: উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক কেন্দ্র কৰি ভাৰত-থাইলেণ্ডৰ সম্পর্কত নতুন গতি

জন জন বিচাৰ
...✍ গুৱাহাটী

ভাৰতৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ সৈতে অধিক ঘনিষ্ঠভাৱে সংযোগ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ভাৰত আৰু থাইলেণ্ডে সহযোগিতাৰ নতুন পথ বিচাৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। এই উদ্দেশ্যে গুৱাহাটী আৰু শ্বিলঙত অনুষ্ঠিত গ্ধঞ্ধ'ব্রহ্মপুত্র—চাও ফ্রায়া সংলাপ'গ্ধঞ্ধত দুয়োখন দেশৰ জ্যেষ্ঠ কূটনীতিবিদ, নীতি-নির্ধাৰক, শিক্ষাবিদ আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্রৰ বিশেষজ্ঞসকলে অংশগ্রহণ কৰে।

২২ আৰু ২৩ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত দুদিনীয়া এই আলোচনাত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক ভাৰতৰ 'পূবমুখী নীতি'ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্র হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লগতে থাইলেণ্ডৰ সৈতে বাণিজ্য, পৰিবহণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন আৰু সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভবিষ্যতে দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ সৈতে সংযোগ

ভাৰতৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ দেশসমূহৰ সৈতে ভৌগোলিকভাৱে তুলনামূলকভাৱে ওচৰত। এই ভৌগোলিক সুবিধাক ব্যৱহাৰ কৰি অঞ্চলটোক আন্তঃৰাষ্ট্রীয় বাণিজ্য আৰু যোগাযোগৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দুৱাৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সম্ভাৱনা সন্দর্ভতো সংলাপত আলোচনা হয়।

গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত প্রথম দিনাৰ আলোচনাত মানৱ সম্পদ, স্বাস্থ্যসেৱা, শিক্ষা আৰু যুৱ উদ্যোগিতাক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হয়। স্থানীয় অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ যুৱ সমাজৰ অংশগ্রহণ, শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ মাজত পোনপটীয়া সহযোগিতা আৰু প্রতিষ্ঠানগত আদান-প্রদান বৃদ্ধিৰ ওপৰত জোৰ দিয়া হয়।

কেৱল চুক্তি নহয়, বাস্তৱ সহযোগিতাত গুৰুত্ব

আলোচনাত অংশগ্রহণকাৰীসকলে কেৱল বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাত সীমাবদ্ধ নাথাকি সেইবোৰ বাস্তৱায়িত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। ইয়াৰ বাবে দুয়োখন দেশৰ প্রতিষ্ঠানসমূহৰ মাজত নিয়মীয়া যোগাযোগ, প্রতিনিধি দলৰ ভ্রমণ আৰু অভিজ্ঞতা বিনিময়ৰ প্রয়োজনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰা হয়।

এই সংলাপ 'এছিয়ান কনফ্লুৱেন্স'ৰ উদ্যোগত ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্রমা মন্ত্রালয় আৰু থাইলেণ্ডৰ বৈদেশিক পৰিক্রমা মন্ত্রালয়ৰ সহযোগিতাত অনুষ্ঠিত হয়। অসম ৰয়েল গ্ল'বেল বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মেঘালয় ইনষ্টিটিউট অৱ গভর্ণেন্সে ইয়াৰ সহ-আয়োজকৰ ভূমিকা পালন কৰে।

গুৱাহাটী-শ্বিলঙৰ পৰা বঙ্গোপসাগৰক লৈ নতুন চিন্তা

২৩ ছেপ্টেম্বৰত শ্বিলঙত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় দিনাৰ আলোচনাত বঙ্গোপসাগৰীয় অঞ্চলত কৌশলগত সহযোগিতা আৰু ভাৰত—থাইলেণ্ডৰ মাজত যোগাযোগ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়।

আলোচনাত দুয়োখন দেশৰ মাজত পোনপটীয়া বিমান যোগাযোগ, আঞ্চলিক পৰিবহণ সংযোগ আৰু বাণিজ্যিক পথ উন্নয়নৰ সম্ভাৱনা সন্দর্ভত মত বিনিময় কৰা হয়। একে সময়তে নবীকৰণযোগ্য শক্তি, পৰিৱেশবান্ধৱ উদ্যোগ, দুর্যোগ ব্যৱস্থাপনা আৰু পর্যটনৰ ক্ষেত্রতো যৌথ উদ্যোগ গ্রহণৰ প্রস্তাৱ আলোচনা কৰা হয়।

শহৰ আৰু প্রদেশ পর্যায়ত অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তোলাৰ জৰিয়তে বাণিজ্য আৰু পর্যটন বৃদ্ধিৰ বিষয়টোও আলোচনাত স্থান লাভ কৰে।

বিমষ্টেক আৰু আইআৰএৰ জৰিয়তে আঞ্চলিক সহযোগিতা

ভাৰত আৰু থাইলেণ্ডৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কৰ লগতে বঙ্গোপসাগৰীয় বহু-খণ্ডীয় কাৰিকৰী আৰু অর্থনৈতিক সহযোগিতা উদ্যোগ শ্চবিমষ্টেকগ্ন আৰু গ্ধঞ্ধভাৱত মহাসাগৰীয় ৰিম সংস্থা শ্চআইঅ'আৰএগ্রঞ্ধঞ্ধৰ দৰে আঞ্চলিক মঞ্চসমূহৰ জৰিয়তে সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ বিষয়েও আলোচনা হয়। অংশগ্রহণকাৰীসকলে মত প্রকাশ কৰে যে আঞ্চলিক মঞ্চসমূহৰ জৰিয়তে বাণিজ্য, যোগাযোগ, শিক্ষা, পৰিৱেশ আৰু দুর্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ দৰে ক্ষেত্রত উমৈহতীয়া স্বার্থসমূহক অধিক সমন্বিত ৰূপ দিব পৰা যায়।

পূবমুখী নীতিত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ গুৰুত্ব

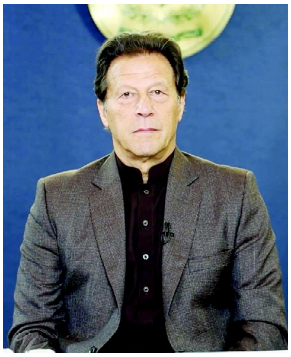
ভাৰতৰ 'পূবমুখী নীতি'ৰ ক্ষেত্রত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ গুৰুত্ব ক্রমাৎ বৃদ্ধি পাইছে। থাইলেণ্ডৰ সৈতে উন্নত যোগাযোগ ব্যৱস্থাই কেৱল দুয়োখন দেশৰ মাজত বাণিজ্যিক সম্পর্ক শক্তিশালী কৰাই নহয়, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অর্থনীতি, পর্যটন, শিক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানতো নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। 'ব্রহ্মপুত্র—চাও ফ্রায়া সংলাপ'ৰ জৰিয়তে দুয়োখন দেশৰ চৰকাৰ, শিক্ষানুষ্ঠান, ব্যৱসায়িক প্রতিষ্ঠান আৰু নাগৰিক সমাজৰ মাজত নিয়মীয়া মত বিনিময়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ সৈতে অধিক ঘনিষ্ঠভাৱে সংযোগ কৰাৰ এই প্রচেষ্টাই ভৱিষ্যতে বাণিজ্য, যোগাযোগ, পর্যটন আৰু সাংস্কৃতিক সম্পর্কৰ নতুন দুৱাৰ মুকলি কৰিব পাৰে।

ইমৰান খানৰ মুক্তিৰ দাবীত পিটিআইৰ ইছলামাবাদ যাত্রা ৪ অক্টোবৰত

ইছলামাবাদ : পাকিস্তানৰ কাৰাগাৰত বন্দী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমৰান খানৰ মুক্তিৰ দাবীত পাকিস্তান তেহৰিক-ই-ইনছাফে (পিটিআই) ঘোষণা কৰা ইছলামাবাদ অভিমুখী বৃহৎ প্রতিবাদী সমদলৰ তাৰিখ পিছুৱাইছে। ২৭ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা থকা এই সমদল এতিয়া ৪ অক্টোবৰত আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে।

দলীয় সূত্রৰ উদ্ধৃতি দি প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসৰি, চৰকাৰে প্রতিবাদ ৰোধ কৰিবলৈ পথ বন্ধ কৰা, বেৰিকেড স্থাপন কৰা আৰু অন্যান্য কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰাৰ পাছতেই পিটিআইয়ে সমদলৰ তাৰিখ সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়।

ইমৰান খান বর্তমান ৰাৱালপিণ্ডিৰ উচ্চ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাযুক্ত আদিয়ালা কাৰাগাৰত বন্দী



হৈ আছে। দুর্নীতিৰ এটা গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পাছত ২০২৩ চনত তেওঁক গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। তৎপ্রেয়ে তেওঁৰ মুক্তিৰ দাবীত চৰকাৰৰ ওপৰত চাপ সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্যৰে ইছলামাবাদলৈ এই বৃহৎ সমদলৰ ঘোষণা কৰিছিল।

দলীয় বৈঠকত প্রতিবাদী সমদল ৪ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। খাইবাৰ পাখতুনখোৱাৰ মুখ্যমন্ত্রী সোহেল আফ্রিদীয়ে ইয়াৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰাৰ কথা। ইয়াৰ পূর্বে পেছোৱাৰত এখন সংবাদমেলত আফ্রিদীয়ে কৈছিল যে পথ বন্ধ কৰা বা চৰকাৰৰ অন্যান্য ব্যৱস্থাৰ পাছতো ইছলামাবাদ অভিমুখী সমদল অব্যাহত থাকিব। তেওঁ দাবী কৰে যে প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ হ'ব।

খাইবাৰ পাখতুনখোৱাৰ সীমান্তৱর্তী পথত গজাল পুতি দিয়া আৰু পথ বন্ধ কৰাৰ খবৰত উদ্বেগ প্রকাশ কৰি তেওঁ প্রশ্ন তোলে-এয়া ৰাজ্যখনক দেশৰ বাকী অংশৰ পৰা পৃথক কৰাৰ কোনো প্রচেষ্টাৰ আৰম্ভণি নেকি?

তৎপ্থ নেতৃত্বই সমদল শান্তিপূর্ণ বুলি দাবী কৰিলেও চৰকাৰ আৰু বিৰোধী দলৰ মাজত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনাই পাকিস্তানৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিক অধিক জটিল কৰি তুলিছে।

৪ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই সমদলত পিটিআইৰ সমর্থকৰ উপস্থিতি আৰু চৰকাৰৰ প্রতিক্রিয়াই দেশখনৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ পৰৱর্তী গতিপথত গুৰুত্বপূর্ণ প্রভাৱ পেলাব পাৰে। ইমৰান খানৰ মুক্তিৰ দাবীক কেন্দ্র কৰি পিটিআইয়ে পুনৰ ৰাজপথলৈ নামিবলৈ সাজু হৈছে, আনহাতে চৰকাৰৰ কঠোৰ ব্যৱস্থাই এই প্রতিবাদক কেনেদৰে মোকাবিলা কৰে, সেয়াই এতিয়া পাকিস্তানৰ ৰাজনীতিত মুখ্য বিষয় হৈ পৰিছে।



৫ অক্টোবৰত মিজোৰামলৈ অমিত শ্বাহ

আইজল: কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অহা ৫ অক্টোবৰত মিজোৰাম ভ্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাজ্যখনত কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰাৰ কথা আছে। চৰকাৰী বিষয়াসকলে শুকুৱাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰে।

বিষয়াসকলৰ মতে, শ্বাহৰ ভ্ৰমণৰ সম্পূৰ্ণ কাৰ্যসূচী এতিয়াও ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত পৰা নাই যদিও সম্ভাব্য ভ্ৰমণক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। ভ্ৰমণকালত ৰাজ্যৰ সমবায় বিভাগৰ অধীনত ৰদ্ৰুপায়ণ কৰা কেইবাটাও প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।

ইফালে, শ্বাহৰ সম্ভাব্য যাত্ৰাপথত যান-বাহন চলাচল সুচাৰুৰদ্ৰুপে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে আইজলৰ উপাযুক্ত লালহ্লিয়াটপুইয়াই এক



নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। ৫ অক্টোবৰত লেংপুইৰ পৰা আইজলৰ ফাল্কলেণ্ডস্থিত যুৱ বিনোদন কেন্দ্ৰলৈকে নিৰ্দিষ্ট পথছোৱাত যান-বাহন ৰখোৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। নিৰ্দেশ অনুসৰি, উক্ত পথত কোনো ধৰণৰ যানজঁট বা যাতায়াতত বাধাৰ সৃষ্টি নকৰিবলৈ চালকসকলক আহ্বান জনোৱা হৈছে। লগতে নিৰ্দিষ্ট যাত্ৰাপথৰ কাষত থকা সকলো পেট্ৰ'ল পাম্প পু অক্টোবৰত বন্ধ ৰখা হ'ব বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিছে।অমিত শ্বাহৰ মিজোৰাম ভ্ৰমণৰ সময়ত কোনবোৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰা হ'ব আৰু আন কি কাৰ্যসূচী থাকিব, সেই বিষয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সম্পূৰ্ণ কাৰ্যসূচী প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত অধিক স্পষ্ট হ'ব।

দলবদলৰ ঘটনাত দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষত নাগালেণ্ড

জন জন বিচাৰ
...নতুন দিল্লী

নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ পিছত ৰাজনৈতিক দল সলনি কৰা নিৰ্বাচিত সাংসদ আৰু বিধায়কৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত ২০২২ৰ পৰা ২০২৬লৈ নাগালেণ্ড দেশৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ঘটনাৰ সাক্ষী হৈছে। এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিফৰ্মছ শ্চএডিআৰগ্ন আৰু নেচনেল ইলেকচন ৰাচৰ এক বিশ্লেষণত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে।

বিশ্লেষণ অনুসৰি, উক্ত সময়ছোৱাত দেশত মুঠ ১১১জন সাংসদ আৰু বিধায়কে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত দল সলনি কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত ২৬জন লোকসভাৰ সাংসদ, ৭জন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আৰু ৭৮জন বিধায়ক আছে।

নাগালেণ্ডত এনে দলবদলৰ ঘটনা ৩২টা, আৰু এই সকলোবোৰেই বিধায়কক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হৈছে। এডিআৰৰ তথ্য অনুসৰি, ইয়াৰে ২৫জন বিধায়ক প্ৰথমে নেশ্যনেলিষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰগ্ৰেছিভ পাৰ্টি এনডিপিপিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল। আনহাতে, নাগা পিপলছ ফ্ৰণ্টে এনপিএফ দল সলনি কৰা বিধায়কৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ,চজনক নিজৰ দললৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে।

পশ্চিমবংগ দ্বিতীয় স্থানত

দলবদলৰ ঘটনাৰ সংখ্যাত পশ্চিমবংগ ২০টা ঘটনাৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে। এই ২০টা ঘটনাই লোকসভাৰ সাংসদক কেন্দ্ৰ কৰি। এডিআৰৰ বিশ্লেষণ অনুসৰি,



আটাইকেইজন সাংসদ প্ৰথমে সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ টিকটত নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু পিছত নেচনেলিষ্ট চিটিজেনছ পাৰ্টি অৰ ইণ্ডিয়ালৈ যোৱাৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে। সাংসদসকলে দলীয় একত্ৰীকৰণৰ দাবী কৰিছে যদিও বিষয়টো লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ বিবেচনাধীন।

তেলেংগানাত ৯টা দলবদলৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আটাইকেইজন বিধায়ক প্ৰথমে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু কংগ্ৰেছলৈ যোৱাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে।

গোৱা আৰু পঞ্জাৱত ৮টাকৈ ঘটনা নথিভুক্ত হৈছে। ইয়াৰ উপৰি মেঘালয়ত ছজন, মণিপুৰত পুজন আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত ৪জন বিধায়কে দল সলনি কৰাৰ তথ্য বিশ্লেষণত প্ৰকাশ পাইছে।

এনডিপিপিৰ পৰা সৰ্বাধিক বিধায়কৰ দলত্যাগ

দলভিত্তিক হিচাপত এনডিপিপিৰ পৰা সৰ্বাধিক **২৫**জন নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিয়ে দল সলনি কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ২০জন আৰু কংগ্ৰেছৰ ১৯জন নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিৰ দলবদলৰ ঘটনা নথিভুক্ত হৈছে। ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিৰ ৯জন, আম আদমি পাৰ্টী আৰু নেশ্যনেলিষ্ট কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ ৭জনকৈ প্ৰতিনিধিৰ দলবদল হৈছে। আনহাতে, দল সলনি কৰি আটাইতকৈ বেছি নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি লাভ কৰা দল হিচাপে এনপিএফৰ নাম আহিছে-৩২জন। বিজেপিয়ে চজ্বজন আৰু নেচনেলিষ্ট চিটিজেনছ পাৰ্টি অৰ ইণ্ডিয়াই ২০জন নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিক লাভ কৰিছে।

দলত্যাগ বিৰোধী ব্যৱস্থা পুনৰীক্ষণৰ পৰামৰ্শ

এডিআৰে জনোৱা মতে, ইয়াৰ বিশ্লেষণত ব্যক্তিগত দলত্যাগ, দলীয় একত্ৰীকৰণ, পদত্যাগৰ পিছত উপ-নিৰ্বাচনত জয় আৰু অযোগ্য ঘোষণাৰ পিছত উপ-নিৰ্বাচনত জয়লাভৰ ঘটনাও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। একেসময়তে সংস্থাটোৱে সতৰ্ক কৰি দিয়ে যে দেশত ৰাজনৈতিক দল সলনি কৰা বিধায়ক-সাংসদৰ কোনো সুসংগঠিত আৰু সহজলভ্য চৰকাৰী তথ্যভাণ্ডাৰ নথকাৰ বাবে এই তালিকা সম্পূৰ্ণ নহ'বও পাৰে।

দলত্যাগ বিৰোধী আইন অধিক কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে এডিআৰে কিছুমান পৰামৰ্শও আগবঢ়াইছে। ইয়াৰ ভিতৰত সাংসদৰ অযোগ্যতাৰ আবেদনত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষমতা অধ্যক্ষৰ পৰিৱৰ্তে নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত ৰাষ্ট্ৰপতিক আৰু বিধায়কৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যপালক দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আছে। লগতে অযোগ্যতাৰ আবেদন নিষ্পত্তিৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা আৰু দলত্যাগ কৰা প্ৰতিনিধিয়ে পুনৰ নিৰ্বাচিত নোহোৱালৈকে চৰকাৰী পদ গ্ৰহণত বিধিনিষেধ আৰোপ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে।

এই সপ্তাহৰ ৰাশিফল

মেষ : আধ্যাত্মিক চেতনা বৃদ্ধি। কৰ্মক্ষেত্ৰত সুনাম অৰ্জন। বিদ্যাৰ্থীৰ শুভ।

বৃষ: ব্যাৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ফল। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সন্মুখীন হব পাৰে। চেষ্টাৰ সফলতা লাভ।

মিথুন: কৰ্মদক্ষতাৰ সুনাম অৰ্জন। আৰ্থিক দিশত সপ্তাহটো শুভ। ব্যাৱসায় বাণিজ্যৰ পৰা লাভ।

কৰ্কট: আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে সপ্তাহটো পাৰ হব। কৰ্মব্যস্ততা বৃদ্ধি। ব্যাৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ।

সিংহ: মানসিক সুখ শান্তি বৃদ্ধি। বিদ্যাৰ্থীৰ বাৰে সপ্তাহটো শুভ। প্ৰতিযগিতামূলক কাৰ্য্যত সফলতা অৰ্জন।

কন্যা : চেষ্টাৰ সফলতা অৰ্জন। মানসিক সুখ শান্তি থাকিব। সন্তানৰ সফলতা থাকিব।

তুলা: কৰ্মক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো শুভ। চেষ্টাৰ বাধাৰ সৃষ্টি হব পাৰে। মানসিক সুস্থিৰতা থাকিব।

বৃশ্চিক: শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো শুভ। অদৰকাৰী খং ৰাগ নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কৰিব। চেষ্টাৰ সফলতা লাভ।

ধনু : ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত মনোনিবেশ থাকিব। মানসিক উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি হব পাৰে। আকস্মিক ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা আছে।

মকৰ: বৈদেশিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জৰিত কাৰঞ্জয্য পৰা লাভ। ব্যাৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি। আদাৰ্কাৰি বাদ বিবাদৰ পৰা আতৰি থাকক।

কুম্ভ : কৰ্মদক্ষতাৰ সমাদৰ লাভ। সামাজিক কাৰ্য্যৰ পৰা লাভ।

মীন: আধ্যাত্মিক চেতনাৰ দ্বাৰা মানসিক শান্তি অৰ্জন। সামাজিক মান মৰ্য্যদা বৃদ্ধি। টোপনিৰ প্ৰতি মনোনিবেশ ৰাখিব।

- হিতেন শৰ্মা শাস্ত্ৰী
অধ্যাপক, বিশ্ব জ্যোতিষ বিদ্যাপীঠ, অসম শাখা
যোগাযোগ : ৯৮৫৪০২৬৭৭৯

বান মোকাবিলাত প্ৰযুক্তিৰ সহায় বিচাৰিছে অসমে: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

জন জন বিচাৰ
...✍ গুৱাহাটী

বানে সৃষ্টি কৰা বিপৰ্যয় অধিক ফলপ্ৰসূভাৱে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে অসমে এতিয়া প্ৰযুক্তিনিৰ্ভৰ সমাধান বিচাৰিছে। শেহতীয়া বানত ৰাজ্যখনত প্ৰাণহানি আৰু সম্পত্তিৰ ব্যাপক ক্ষতি হোৱাৰ পাছত বানৰ আগতীয়া প্ৰস্তুতি অধিক শক্তিশালী কৰাটো চৰকাৰৰ অন্যতম অগ্ৰাধিকাৰ হৈ পৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুকুৰবাৰে কয়।

গুৱাহাটীত North-East Seva First Innovation Challenge (NESFIC) শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে যুৱ উদ্ভাৱকসকলে বান সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰিক আৰু মাটিৰ সৈতে সংযোগ থকা সমাধান উলিয়াব বুলি তেওঁ আশাবাদী।

পাঁচ-ছয় ঘণ্টাৰ আগজাননীও হ'ব পাৰে জীৱনদায়ক

শেহতীয়া বানৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে শিৰসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত সংঘটিত বানৰ সময়ত যদি পাঁচ বা ছয় ঘণ্টা আগতে সতৰ্কবাণী লাভ কৰা গ'লহেঁতেন, তেন্তে বহু লোকৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি ৰক্ষা কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন।



তেওঁৰ মতে, বানৰ আগজাননী ব্যৱস্থাত সামান্য সময়ৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিলেও জিলা প্ৰশাসনে মানুহক সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা, ঘৰ-দুৱাৰ আৰু জীৱ-জন্তু ৰক্ষা কৰা তথা অন্যান্য জৰুৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে অধিক সময় লাভ কৰিব।

উপগ্ৰহ, ড্ৰোন আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ব্যৱহাৰ

বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগে আৰম্ভ কৰা উদ্ভাৱনী প্ৰত্যাহ্বানত বান ব্যৱস্থাপনা আৰু আগতীয়া সতৰ্কবাণীৰ লগতে উপগ্ৰহ, ড্ৰোন আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে।

কৃষিক্ষেত্ৰত শস্যৰ স্বাস্থ্যঞ্জয নিৰীক্ষণ, জলাভূমিৰ মানচিত্ৰ প্ৰস্তুত, চৰকাৰী ভূমিৰ বেদখল চিনাক্তকৰণ আৰু বান নিয়ন্ত্ৰণৰ দৰে ক্ষেত্ৰতো প্ৰযুক্তিভিত্তিক সমাধান বিচৰা হৈছে।

উদ্ভাৱন কেৱল নতুন বস্তু সৃষ্টি কৰাৰ বাবে নহয়

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে NESFICৰ উদ্দেশ্য কেৱল নতুন প্ৰযুক্তি বা নতুন সামগ্ৰী উদ্ভাৱন কৰাই নহয়। মানুহ, চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰু উদ্যোগসমূহে সন্মুখীন হোৱা বাস্তৱ সমস্যাসমূহ চিনাক্ত কৰি মাটিত কাৰ্যকৰীভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব পৰা সমাধান উলিয়োৱাটোৱেই এই উদ্যোগৰ মূল লক্ষ্য।

২০২৬ চনৰ এই উদ্ভাৱনী প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে শুকুৰবাৰৰ পৰা আবেদন গ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে।

কৃষি, জলবায়ু আৰু পৰিৱেশ, স্বাস্থ্যসেৱা, যাতায়াত, পৰ্যটন আৰু ডিজিটেল প্ৰযুক্তিকে ধৰি কেইবাটাও ক্ষেত্ৰ এই প্ৰত্যাহ্বানৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে।

অসমৰ বাবে বান নতুন সমস্যা নহয়; কিন্তু আগতীয়া সতৰ্কবাণী, তথ্য-প্ৰযুক্তি আৰু দ্ৰুত প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাক একত্ৰিত কৰি বানৰ ক্ষতি হ্ৰাস কৰাৰ নতুন পথ বিচৰাটো এতিয়া চৰকাৰৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষ্য হৈ পৰিছে।

'শিল্পীসকল অৰুণাচলৰ অতিথি': ছিকিমৰ বেপাৰৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ অভিযোগত ন্যায়ৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ

ইটানগৰ: ছিকিমৰ জনপ্ৰিয় বেপাৰ ইউজেন নামগ্যাল ভুটিয়া, জনপ্ৰিয়ভাৱে ইউএনবি নামেৰে পৰিচিত, আৰু তেওঁৰ পৰিচালকৰ ওপৰত সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘটনাটোৰ ন্যায়সংগত তদন্ত আৰু দোষীৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিছে।

অভিযোগ অনুসৰি, লোৱাৰ দিবাং ভেলী জিলাৰ তিৰাৰী গাঁওৰ ওচৰত এই ঘটনা সংঘটিত হয়। ইউএনবি আৰু তেওঁৰ দলটোৱে আনিনি শীতকালীন উৎসৱত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি ৰয়িঙলৈ উভতি অহাৰ সময়তে তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ কৰা হৈছে।

'অৰুণাচললৈ অহা শিল্পীসকল আমাৰ অতিথি'

ঘটনাটোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰে কয় যে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ অৰুণাচললৈ অহা শিল্পীসকল ৰাজ্যখনৰ অতিথি। তেওঁলোকক সন্মান আৰু নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাটো ৰাজ্যখনৰ দায়িত্ব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে।

খাণ্ডুৰে কয় যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অৰ্থনীতি আৰু জীৱিকাৰ ক্ষেত্ৰত পৰ্যটনৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট। সেয়েহে ৰাজ্যখনলৈ অহা প্ৰতিজন পৰ্যটক, শিল্পী আৰু অতিথিক গ্ধৰ্দ্ধ'অতিথি দেৱো ভৱঃ'ৰ মনোভাৱেৰে আদৰণি জনোৱা উচিত।

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে জনায় যে তেওঁ ইতিমধ্যে ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাং গোলাযৰ সৈতে এই ঘটনাক লৈ কথা পাতিছে। ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ন্যায় নিদ্ৰিশ্চত কৰাৰ আশ্বাস তেওঁ ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক দিছে।

আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ

ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু আক্ৰমণৰ অভিযোগৰ সম্পূৰ্ণ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে।

ঘটনাটোত কোন কোন লোক জড়িত আছিল, আক্ৰমণৰ সঠিক কাৰণ কি আৰু অভিযোগসমূহৰ সত্যতা কিমান-এই সকলো বিষয় তদন্তৰ জৰিয়তে স্পষ্ট হ'ব।

উত্তৰ-পূৰৰ শিল্পীসকলৰ নিৰাপত্তাক লৈও প্ৰশ্ন

ছিকিমৰ এগৰাকী শিল্পীয়ে অৰুণাচলত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহি আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাটোৱে উত্তৰ-পূৰৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মাজত চলি থকা সাংস্কৃতিক আদান-প্ৰদানৰ পৰিৱেশত শিল্পী আৰু অতিথিৰ নিৰাপত্তাৰ বিষয়টোও পুনৰ চৰ্চালৈ আনিছে। উত্তৰ-পূৰৰ ৰাজ্যসমূহৰ মাজত সংগীত, উৎসৱ আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী হৈ আহিছে। এনে সময়ত অৰুণাচল চৰকাৰে ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায় নিশ্চিত কৰাৰ দিয়া আশ্বাসে বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে। এতিয়া আৰক্ষীৰ তদন্তৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব ঘটনাটোৰপ্ৰকৃত সত্য উদঘাটন আৰু দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে পৰৱৰ্তী আইনী ব্যৱস্থা।

সম্পাদকীয়

বৈভৱৰ বাবে অপেক্ষা কিমান দীঘলীয়া ?

ভাৰতীয় ক্রিকেটত প্রতিভাৰ অভাৱ নাই, কিন্তু প্রতিভাক সুযোগ দিয়াৰ ক্ষেত্রত সিদ্ধান্ত কেতিয়াবা অধিক কঠিন হৈ পৰে। আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত টি-২০ শৃংখলাত ১৫ বছৰীয়া বৈভৱ সূর্যবংশীয়ে এখনো খেলাৰ সুযোগ নোপোৱাটোৱে সেই প্রশ্নটোক পুনৰ সন্মুখলৈ আনিছে-ভৱিষ্যতৰ তাৰকাক কেতিয়া সুযোগ দিয়া হ'ব?

জিম্বাবুৱে ভ্রমণত বৈভৱে অসাধাৰণ প্রদর্শনেৰে শৃংখলাৰ শ্রেষ্ঠ খেলু�ৰৈৰ সন্মান লাভ কৰিছিল। ১৯৬.১০ ষ্ট্রাইক ৰেটে ১৫১ ৰান সংগ্রহ কৰা এই কিশোৰ প্রতিভাই ইতিমধ্যে নিজৰ সামর্থৰ পৰিচয় দিছে। তথাপি সঞ্জু ছেমছনৰ দললৈ প্রত্যাৱর্তনৰ পিছত তেওঁ মূল একাদশৰ বাহিৰত থাকিল।

মুখ্য প্রশিক্ষক গৌতম গম্ভীৰে সিদ্ধান্তটোৰ ব্যাখ্যা দি কয় যে ছেমছনে বহু বছৰ ধৰি ভাৰতৰ হৈ নিজৰ সামর্থ্য প্রমাণ কৰিছে আৰু বিশ্বকাপ জয়ী দলৰ সংমিশ্রণলৈ উভতি যোৱাটো তেওঁৰ লক্ষ্য আছিল। এই যুক্তিৰ ক্রিকেটীয় ভিত্তি নিশ্চয় আছে। ছেমছনেও আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে তিনিখন খেলত ১১৭ ৰান কৰি দুটা অর্ধশতকৰে নিজৰ দাবী শক্তিশালী কৰিছে।

কিন্তু আন এটা প্রশ্নও সমানেই গুৰুত্বপূর্ণ-এটা দলত অভিজ্ঞতা আৰু বর্তমানৰ ফলাফলৰ মূল্যায়নৰ লগতে উদীয়মান প্রতিভাৰ বিকাশৰ পথটো কেনেকৈ মুকলি কৰা হ'ব?

গম্ভীৰে স্পষ্ট কৰিছে যে বৈভৱক নিজৰ সুযোগৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু সুযোগ আহিলে তেওঁক দীঘলীয়া সময় দিয়াৰ পৰিকল্পনা আছে। কথাটো আশাব্যক। কিন্তু প্রতিভাৰ বিকাশ কেৱল অপেক্ষাৰ ওপৰত নির্ভৰ নকৰে; সঠিক সময়ত সুযোগ, দায়িত্ব আৰু বিশ্বাসো প্রয়োজন।

ভাৰতীয় ক্রিকেটৰ শক্তি হৈছে ইয়াৰ গভীৰ প্রতিভাৰ ভঁৰাল। সেয়ে বৈভৱৰ দৰে কিশোৰ প্রতিভাৰ ক্ষেত্রত প্রশ্নটো কেৱল তেওঁ আজি খেলিব নে নাই, সেয়া নহয়। প্রশ্নটো হ'ল-তেওঁৰ দৰে প্রতিভাক ভৱিষ্যতৰ বাবে কেনেদৰে গঢ়ি তোলা হ'ব?

সঞ্জু বনাম বৈভৱক লৈ বিতর্ক সৃষ্টি কৰাৰ সলনি ভাৰতীয় ক্রিকেটৰ উচিত হ'ব দুয়োৰে বাবে উপযুক্ত ভূমিকা আৰু পথ নির্ধাৰণ কৰা। কাৰণ সুযোগৰ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় ঠিকেই, কিন্তু অপেক্ষাই যাতে প্রতিভাৰ গতি থমকাই নিদিয়ে-সেই দায়িত্ব দলীয় ব্যৱস্থাপনাৰো।

বিশ্বমঞ্চত মোদীৰ প্রভাৱ, দেশত ৰাজনীতিৰ নতুন সমীকৰণ

জন জন বিচাৰ
...ডিমেশ চতুর্বেদী

নৰেন্দ্র মোদীৰ ৰাজনৈতিক যাত্রা ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ অন্যতম গুৰুত্বপূর্ণ অধ্যায়। গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে দীঘলীয়া সময়ৰ পিছত চন্ধৱচ্ছ চনত দেশৰ প্রধানমন্ত্রী হোৱা মোদীয়ে চন্ধৱজ্ঞ চনত পুনৰ কেন্দ্রত চৰকাৰ গঠন কৰে আৰু চন্ধৱচ্ছ চনৰ জ্ঞ জুনত তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্রধানমন্ত্রী হিচাপে শপত গ্রহণ কৰে।

তিনিটা কার্যকালৰ এই যাত্রাত তেওঁৰ ৰাজনৈতিক পৰিচয় কেৱল নির্বাচনী ৰাজনীতিৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই। বৈদেশিক নীতি, ডিজিটেল প্রশাসন, আন্তঃগাঁথনি, কল্যাণমূলক আঁচনি, সাংস্কৃতিক ৰাজনীতি, সামাজিক মাধ্যম আৰু বৃহৎ জনসংযোগ-প্রায় প্রতিটো ক্ষেত্রতে তেওঁৰ নেতৃত্বৰ এক নির্দিষ্ট ছাপ পৰিছে। কিন্তু এই প্রভাৱৰ মূল্যায়ন কৰোঁতে কেৱল সমর্থকৰ দৃষ্টিভংগী অথবা বিৰোধীৰ অভিযোগ-এটামাত্র দিশত ৰৈ যোৱাটোও যথেষ্ট নহয়। মোদী যুগক বুজিবলৈ সফলতা, বিতর্ক, নীতি আৰু তাৰ প্রভাৱ-সকলোকে একেলগে চাব লাগিব।

গুটিনিৰপেক্ষতাৰ পৰা কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনলৈ

মোদী চৰকাৰৰ বৈদেশিক নীতিৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টঞ্জয হৈছে একে সময়তে বিভিন্ন শক্তিশালী দেশৰ সৈতে সম্পর্ক ৰক্ষা কৰাৰ চেষ্টা। ভাৰত আমেৰিকা, ৰাছিয়া, ইউৰোপ, জাপান, ইজৰাইল, উপসাগৰীয় দেশ আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ দেশসমূহৰ সৈতে একাধিক ক্ষেত্রত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰিছে।

ইয়াক বহু বিশ্লেষকে 'বহুমুখী সংযুক্তি' বা 'মাল্টি-এলাইনমেণ্ট' বুলি ব্যাখ্যা কৰে। অৱশ্যে এই নীতিক ভাৰতৰ পৰম্পৰাগত গুটিনিৰপেক্ষতাৰ সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ বুলি কোৱাটো সৰলীকৰণ হ'ব। বৈদেশিক পৰিক্রমা মন্ত্রালয়ৰ নথিতো ভাৰতৰ কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন, জাতীয় স্বার্থ আৰু পৰিবর্তিত আন্তঃৰাষ্ট্রীয় পৰিস্থিতিৰ সৈতে বাস্তৱবাদীভাৱে সম্পর্ক গঢ়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে।

ৰাছিয়া-ইউক্রেইন সংঘাতৰ সময়ত ভাৰতৰ স্থিতি ইয়াৰ এটা উল্লেখযোগ্য উদাহৰণ। পশ্চিমীয়া দেশসমূহৰ সৈতে ভাৰতৰ কৌশলগত সম্পর্ক গভীৰ হৈ থকাৰ সময়তো ৰাছিয়াৰ সৈতে শক্তি, প্রতিৰক্ষা আৰু অন্যান্য ক্ষেত্রৰ সম্পর্ক সম্পূর্ণৰূপে পৰিত্যাগ কৰা হোৱা নাই। এই নীতিক সমর্থকসকলে 'কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন' বুলি ব্যাখ্যা কৰে।

'গ্লবৈল ছাউথ'ৰ কণ্ঠস্বৰ

মোদী চৰকাৰৰ বৈদেশিক নীতিৰ আন এটা উল্লেখযোগ্য দিশ হৈছে উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ সমস্যা আন্তঃৰাষ্ট্রীয় মঞ্চত উত্থাপন কৰাৰ চেষ্টা। চন্ধৱচ্চ চনত ভাৰতৰ উদ্যোগত 'ভইচ অৱ গ্ল'বেল ছাউথ ছামিট' অনুষ্ঠিত হৈছিল। উন্নয়ন, খাদ্য আৰু শক্তি সুৰক্ষা, ঋণ, জলবায়ু পৰিবর্তন আৰু বিশ্ব শাসন ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰৰ দৰে বিষয়ত উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ অগ্রাধিকাৰক আলোচনালৈ অনা হৈছিল।

এই ক্ষেত্রত মোদী নেতৃত্বৰ এটা লক্ষ্য স্পষ্ট-ভাৰতক কেৱল দক্ষিণ এছিয়াৰ শক্তি হিচাপে নহয়, বৰং বিশ্বৰ বিভিন্ন শক্তিৰ মাজত এক গুৰুত্বপূর্ণ অংশীদাৰ হিচাপে প্রতিষ্ঠা কৰা।

জনসংযোগৰ নতুন ৰাজনীতি

মোদীৰ ৰাজনৈতিক কৌশলৰ অন্যতম শক্তিশালী দিশ হৈছে জনসংযোগ। 'মন কি বাত', বৃহৎ জনসভা, সামাজিক মাধ্যম আৰু দৃশ্যমান ৰাজনৈতিক কার্যসূচীৰ জৰিয়তে তেওঁ পোনপটীয়াকৈ জনসাধাৰণৰ সৈতে যোগাযোগৰ এক শক্তিশালী পৰিকাঠামো গঢ়ি তুলিছে।

ইয়াৰ ফলত পৰম্পৰাগত ৰাজনৈতিক মধ্যস্থতাকাৰীৰ ভূমিকা বহু ক্ষেত্রত সলনি হৈছে। কোনো নীতি বা চৰকাৰী আঁচনিৰ বার্তা দলীয় সংগঠন, সংবাদমাধ্যম বা স্থানীয় ৰাজনৈতিক নেতাৰ মাজেৰে যোৱাৰ পৰিবর্তে পোনপটীয়াকৈ প্রধানমন্ত্রীৰ পৰা নাগৰিকৰ ওচৰলৈ গৈছে।

এই মডেলৰ সমর্থকসকলে ইয়াক শক্তিশালী জনসংযোগ বুলি দেখে। সমালোচকসকলে অৱশ্যে কয় যে ৰাজনীতি যদি অতি বেছি ব্যক্তিকেন্দ্রিক যোগাযোগৰ ওপৰত নির্ভৰশীল হয়, তেন্তে নীতি আৰু প্রতিষ্ঠানৰ তুলনাত ব্যক্তিৰ ভাবমূর্তি অধিক গুৰুত্বপূর্ণ হৈ পৰাৰ আশংকা থাকে।

সিদ্ধান্ত আৰু বিতর্ক-দুয়ো একেলগে

মোদী চৰকাৰৰ কেইবাটাও সিদ্ধান্ত ভাৰতীয় ৰাজনীতি আৰু অর্থনীতিত গভীৰ প্রভাৱ পেলোৱা বুলি ধৰা হয়। জিএছটি, নোটবন্দী, ধাৰা জ্ঞ্জ্ঞৰ সাংবিধানিক পৰিবর্তন, ডিজিটেল ভাৰত, জন-ধন আঁচনি, প্রত্যক্ষ লাভ হস্তান্তৰ, নতুন অপৰাধ আইন আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন-এইবোৰৰ প্রতিটোৱেই নিজস্বভাৱে বৃহৎ নীতি-পদক্ষেপ।

কিছুমান সিদ্ধান্তক চৰকাৰে প্রশাসনিক সৰলীকৰণ, স্বচ্ছতা বা ৰাষ্ট্রীয় একীকৰণৰ পদক্ষেপ হিচাপে ব্যাখ্যা কৰিছে। আনহাতে বিৰোধী দল আৰু সমালোচকসকলে কিছুমান সিদ্ধান্তৰ সামাজিক, অর্থনৈতিক বা সাংবিধানিক প্রভাৱক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন কৰিছে।

সেয়েহে 'সাহসী সিদ্ধান্ত' বা 'ভুল সিদ্ধান্ত'-এটা শব্দৰে এই পদক্ষেপসমূহৰ মূল্যায়ন কৰাতকৈ প্রতিটো নীতিৰ উদ্দেশ্য, বাস্তৱ ফলাফল আৰু জনসাধাৰণৰ ওপৰত প্রভাৱ পৃথকে পৰীক্ষা কৰাটো অধিক যুক্তিসংগত।

ডিজিটেল ভাৰত : প্রশাসনৰ নতুন মুখ

ডিজিটেল প্রযুক্তি মোদী চৰকাৰৰ শাসন মডেলৰ অন্যতম দৃশ্যমান অংশ। আধাৰ, জন-ধন, মোবাইল সংযোগ আৰু প্রত্যক্ষ লাভ হস্তান্তৰৰ সংযোগে চৰকাৰী সাহায্যৰ ধন পোনপটীয়াকৈ হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টলৈ পঠিওৱাৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিছে।

ইউপিআইৰ বিস্তাৰো এই পৰিবর্তনৰ অন্যতম উদাহৰণ। এনপিচিআইৰ তথ্য অনুসৰি চন্ধৱচ্ছ চনৰ আগষ্ট মাহত ইউপিআইত জ্ঞ্জ্ঞচটা বেংক সক্রিয় আছিল আৰু মাহটোত চচ্ছ,গুত্তজ্জ.জ্ঞৰ মিলিয়ন লেনদেন সম্পন্ন হৈছিল। এই পৰিবর্তনে নগদবিহীন লেনদেন, ক্ষুদ্র ব্যৱসায় আৰু ডিজিটেল অর্থনীতিক নতুন গতি দিছে। কিন্তু ডিজিটেল ব্যৱস্থাৰ বিস্তাৰৰ লগে লগে তথ্য-গোপনীয়তা, চাইবাৰ সুৰক্ষা আৰু ডিজিটেল বিভাজনৰ প্রশ্নও গুৰুত্বপূর্ণ হৈ পৰিছে।

কল্যাণমূলক ৰাজনীতি আৰু 'লাভার্থী' ভিত্তি

উজ্জবলা, জন-ধন, প্রধানমন্ত্রী আৱাস, বিনামূলীয়া খাদ্যশস্য, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু বিভিন্ন প্রত্যক্ষ সাহায্য আঁচনিৰ জৰিয়তে চৰকাৰে বৃহৎ সংখ্যক নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি কল্যাণমূলক নীতি ৰূদ্রপায়ণ কৰিছে।

এই আঁচনিসমূহে এক নতুন 'লাভার্থী' ৰাজনীতিৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণত আলোচনা হয়। ইয়াৰ অর্থ হৈছে-জাতি, ধর্ম বা পৰম্পৰাগত ভোটবেংকৰ বাহিৰেও চৰকাৰী আঁচনিৰ প্রত্যক্ষ সুবিধা লাভ কৰা লোকসকল এক গুৰুত্বপূর্ণ ৰাজনৈতিক গোটত পৰিণত হৈছে।

অৱশ্যে আঁচনি ঘোষণা আৰু বাস্তৱ সুবিধা লাভ-দুয়োটাৰ মাজত পার্থক্য আছে। সেয়েহে কোনো আঁচনিৰ মূল্যায়নত কিমানজনক ঘোষণা কৰা হৈছে তাৰ লগতে কিমানজনে বাস্তৱতে সুবিধা পাইছে, সুবিধাৰ মান কেনেকুৱা আৰু সেই সুবিধা কিমান দিন টিকিছে-এইবোৰো বিবেচনা কৰিব লাগিব।

আন্তঃগাঁথনি : দৃশ্যমান পৰিবর্তনৰ ৰাজনীতি

ৰাষ্ট্রীয় ঘাইপথ, ৰেল, বিমানবন্দৰ, বন্দৰ, মালবাহী কৰিডৰ আৰু নগৰীয়া আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ গুৰুত্ব মোদী যুগৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য। 'পিএম গতিশক্তি'ৰ দৰে পৰিকল্পনাই বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনি প্রকল্পক একে পৰিকাঠামোৰ অধীনত সমন্বয় কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে। ইয়াৰ ৰাজনৈতিক গুৰুত্বও আছে। কাৰণ পথ, ৰেল, বিমানবন্দৰ বা নতুন নগৰীয়া প্রকল্প নাগৰিকৰ দৈনন্দিন জীবনত দৃশ্যমান। ফলত উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কেৱল পৰিসংখ্যাৰ বিষয় হৈ নাথাকি চকুৰ সন্মুখৰ বাস্তৱ পৰিবর্তনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰে।

হিন্দুত্ব, সংস্কৃতি আৰু ৰাজনৈতিক পৰিচয়

মোদী যুগৰ ৰাজনীতিৰ আলোচনা হিন্দুত্ব আৰু সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ প্রশ্ন অবিহনে সম্পূর্ণ নহয়। ৰাম মন্দিৰ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, যোগ, ভাৰতীয় পৰম্পৰা আৰু ৰাষ্ট্রীয় গৌৰৱৰ প্রচাৰে বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক ৰয়ানত বিশেষ স্থান লাভ কৰিছে।

সমর্থকসকলে ইয়াক ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ আত্মবিশ্বাসৰ পুনৰুত্থান হিচাপে ব্যাখ্যা কৰে। আনহাতে সমালোচকসকলে ধর্মীয় মেৰুকৰণ, সংখ্যালঘুৰ অধিকাৰ আৰু ধর্মনিৰপেক্ষ সাংবিধানিক কাঠামোৰ ওপৰত ইয়াৰ সম্ভাব্য প্রভাৱক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন কৰে।

এই বিতর্ক ভাৰতীয় গণতন্ত্রৰ বাবে গুৰুত্বপূর্ণ। কাৰণ সাংস্কৃতিক গৌৰৱ আৰু সকলো নাগৰিকৰ সমান সাংবিধানিক অধিকাৰ-দুয়োটাৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো যিকোনো চৰকাৰৰ দায়িত্ব।



মুম্বাইত গণেশ চতুৰ্থী উৎসৱৰ অন্তিম দিনা বিসৰ্জনৰ বাবে ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি কঢ়িয়াই নিয়া ভক্তসকল।

মধুপুৰ সত্ৰৰ পুনৰ্নিৰ্মাণত অসম-বংগ একেলগে

কোচবিহাৰ: মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বৈষ্ণৱীয় আদৰ্শ আৰু ঐতিহ্যৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত কোচবিহাৰৰ ঐতিহাসিক মধুপুৰ সত্ৰৰ সংৰক্ষণ আৰু পুনৰ্নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰু পদ্মিশ্চমবংগ চৰকাৰে একেলগে কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। পদ্মিশ্চমবংগৰ মন্ত্ৰী নিশীথ প্ৰামাণিকে প্ৰকাশ কৰা মতে, সত্ৰখনৰ উন্নয়নৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যই এক যৌথ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব।

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মধুপুৰ সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি সত্ৰখনৰ সংৰক্ষণ আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত পদ্মিশ্চমবংগ চৰকাৰৰ সহযোগিতা বিচাৰিছিল। তেওঁ সত্ৰখনৰ বাবে অধিক ভূমি উপলব্ধ হ'লে ইয়াক বৃহৎ পৰিসৰত গঢ়ি তোলাৰ কথা উল্লেখ কৰে।

মন্ত্ৰী নিশীথ প্ৰামাণিকৰ মতে, মধুপুৰ সত্ৰলৈ অসমৰ পৰা বহুবৰ বিভিন্ন সময়ত বহু ভক্ত আহে। সেয়ে সত্ৰখনৰ ধৰ্মীয় গুৰুত্বৰ লগতে ইয়াৰ ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিক তাৎপৰ্যও বিবেচনা কৰি উন্নয়নৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে।

সত্ৰৰ আশে-পাশে থকা ভূমিৰ একাংশ বেদখলৰ অধীনত থকা বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰামাণিকে কয় যে বেদখল আঁতৰোৱাৰ বিষয়টোও দুয়োখন চৰকাৰৰ আলোচনাত স্থান পাইছে। অৱশ্যে এই প্ৰক্ৰিয়াত সংশ্লিষ্ট লোকসকল যাতে অযথা ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয়, সেই দিশটো বিবেচনাত ৰখাৰ কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। প্ৰয়োজন অনুসৰি স্থানান্তৰ বা ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থাও চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বুলি তেওঁ কয়।

তেওঁৰ মতে, মধুপুৰ সত্ৰৰ উন্নয়নৰ বাবে এখন বিস্তৃত নক্সা প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত অসম আৰু পদ্মিশ্চমবংগ চৰকাৰে ইয়াৰ ৰূপায়ণৰ বাবে যৌথ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব।

কেৱল সত্ৰ নহয়, সাংস্কৃতিক সংযোগৰো কেন্দ্ৰ

মধুপুৰ সত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ মাজত



এক বৃহত্তৰ ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক পৰ্যটন সংযোগ গঢ়ি তোলাৰ প্ৰস্তাৱো উত্থাপিত হৈছে। ইয়াৰ অংশ হিচাপে অসমৰ নগাঁও জিলাৰ বটদ্ৰৱা থান-শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান-আৰু মধুপুৰ সত্ৰক একেটা ধৰ্মীয় পৰ্যটন পৰিক্ৰমাৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ কথা আলোচনা হৈছে।

মধুপুৰ সত্ৰৰ উন্নয়নৰ বাবে পূৰ্বে ত্ৰি কোটি টকা ঘোষণা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰামাণিকে কয় যে প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট ব্যয়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই। তেওঁৰ মতে, মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় ধন ব্যয় কৰাৰ বাবে চৰকাৰ সাজু থকাৰ কথা জনাইছে।

মধুপুৰ সত্ৰৰ পুনৰ্নিৰ্মাণে কেৱল এটা ঐতিহাসিক ধৰ্মীয় স্থানৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাই নহয়, শংকৰদেৱৰ বৈষ্ণৱীয় ঐতিহ্যৰ সৈতে জড়িত অসম আৰু পদ্মিশ্চমবংগৰ ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কক অধিক দৃঢ় কৰাৰ সম্ভাৱনা সৃষ্টি কৰিছে।

GAURANSHI
INDUSTRIES

Gunika™

Purity in Every Drop, Nature in Every Product.

100% NATURAL

PURE NATURAL GOODNESS







NO ADDITIVES
BOOSTS IMMUNITY
RICH IN ANTIOXIDANTS
ECO FRIENDLY



TEA

NAME	MAKHANA (FOX NUT SUPERFOOD)	ASSAM CTC TEA	ASSAM CTC TEA
SIZE	200gm	250gm	100gm

HONEY







NAME	MORINGA HONEY	TULSI HONEY
SIZE	200gm	200gm







NAME	MUSTARD HONEY	LITCHI HONEY	WILD FOREST HONEY
SIZE	200gm	200gm	200gm

RAW & UNPROCESSED | PURE & NATURAL | DIRECTLY FROM OUR FARMS | TRUSTED BY THOUSANDS

3rd Floor, IIT Road,
Jayguru, Amingaon,
Kamrup, Assam - 781031, India

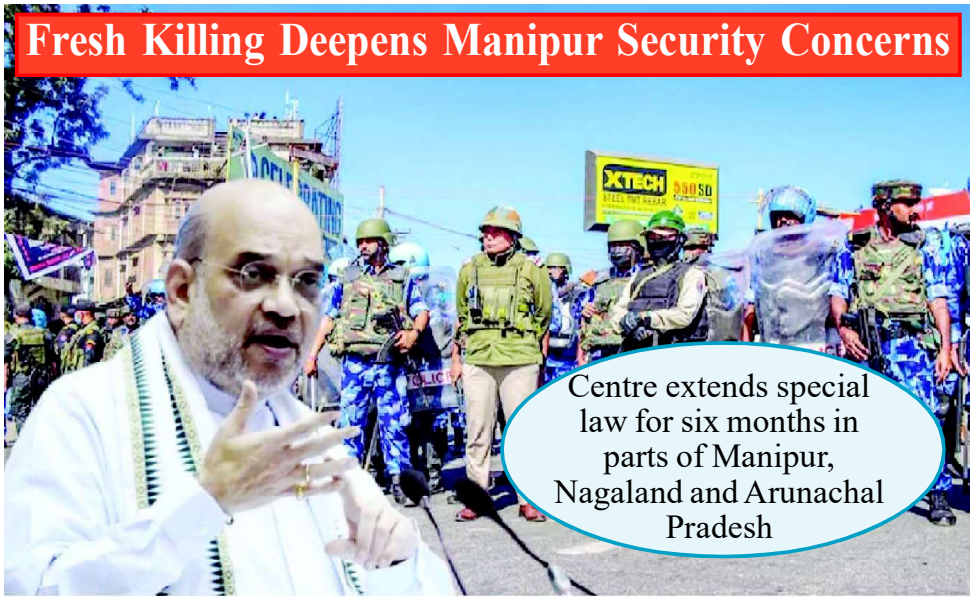
Contact :
+91-88224 20619

E-Mail :
gauranshiind@gmail.com
www.gauranshiindustries.com

VOICE OF ALL, FOR ALL
JAN JAN VICHAR
WEEKLY
Guwahati, Friday, 18 September 2026

AFSPA Extended Across Northeast

Jan Jan Vichar
...✍New Delhi/Imphal



The security situation in the Northeast remains a major concern as the Centre has extended the Armed Forces (Special Powers) Act, or AFSPA, for another six months in parts of Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh, even as the killing of four civilians in Manipur's Kamjong district has brought fresh attention to the fragile security situation along the India-Myanmar border.

According to the Ministry of Home Affairs notification, the extension will take effect from October 1, 2026. In Manipur, the law will continue to apply to most of the state, with areas under 13 police stations in five districts kept outside its ambit. The government has classified the remaining areas as "disturbed areas" under Section 3 of the AFSPA.

Nine Nagaland districts under AFSPA

In Nagaland, AFSPA has been extended to nine districts-Dimapur, Newland, Chumoukedima, Mon, Kiphire, Noklak, Phek, Peren and Meluri. Areas under 21 police stations in five other districts have also been covered by the notification.

In Arunachal Pradesh, the extension covers Tirap, Changlang and Longding districts. The latest move comes despite the Centre's stated objective of gradually reducing the geographical spread of AFSPA in the Northeast. Union Home Minister Amit Shah has previously said that the government expects to remove AFSPA from most of the region, apart from one or two states, in the coming year.

Four civilians killed in Kamjong

The AFSPA extension coincides with a deadly incident in Manipur's Kamjong district, where the bodies of four Tangkhul Naga civilians were recovered near the India-Myanmar border. Police and multiple reports identified the victims as Phami Jajo, Ningthem Kashak, Betterson Jajo and Vareishim Jajo. Two of the victims were reported to be father and son.

The incident took place at Pilong village, around 35 kilometres from the Kamjong district headquarters. Police suspect that armed militants operating from across the Myanmar border may have been involved. The allegation by local Naga organisations regarding the involvement of the Myanmar-based Kuki National Army-Burma faction has not been independently verified. A 24-hour shutdown was subsequently called by the Tangkhul Naga Long in protest against the killings, with essential services exempted.

Security challenge remains

The simultaneous extension of AFSPA and the latest civilian killings underline the continuing security challenges confronting parts of the Northeast. While the Centre has repeatedly spoken of restoring normalcy and reducing the areas under the special law, incidents of violence along vulnerable border and hill regions continue to test that objective. For residents of affected areas, the immediate concerns remain security, protection of civilians and accountability for violence. The latest developments also place renewed focus on how effectively security measures can be balanced with the return of lasting peace and normal civilian life in the region.

Arunachal CM likely to visit Siang, Upper Siang amid concerns over mega dam project

Itanagar: Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu is likely to visit Siang, Upper Siang and East Siang districts to meet local residents, village elders, civil society organisations and community groups raising concerns over the proposed Siang Upper Multipurpose Project (SUMP).

Khandu has said the state government is open to dialogue on the proposed mega project and is willing to hear concerns raised by organisations including the Adi Bane Kebang (ABK) and other community bodies from the Siang region.

The Chief Minister has maintained that the government is not forcing the SUMP project on local people and has indicated that discussions and consultations will continue.The proposed project, however, has faced opposition from sections of local residents and organisations, particularly over the ongoing Pre-Feasibility Report (PFR) activities. The ABK-U has publicly called for the PFR activities to be stopped. The SUMP issue has emerged as a major point of discussion in Siang and Upper Siang, with government representatives stressing dialogue while opponents continue to raise concerns over the proposed project and survey-related activities. Meanwhile, the Arunachal Pradesh Cabinet recently approved the constitution of an Empowered High-Level Committee to guide and coordinate the PFR survey and related activities for the SUMP and facilitate engagement with communities in Siang and Upper Siang.

‘Northeast is not where India ends, but where India begins’

Gen Upendra Dwivedi in Guwahati

Jan Jan Vichar
...✍Guwahati



Former Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi (Retd) on September 25 described the Northeast as a "true gateway" to India, calling on young people to combine technological skills with adaptability, ability and a strong grounding in Indian values.

Dwivedi was speaking at 'Namami Bharatam', a collective singing programme organised by Vidya Bharati Northeast Region at the Srimanta Sankaradeva International Auditorium in Guwahati to mark the 150th anniversary of Vande Mataram.

Addressing the gathering, Dwivedi said, "The Northeast is not the place where India ends, but the place from where India begins. It is the true gateway to the nation."

He said he was addressing the gathering not merely as a former Army chief but as an alumnus of Saraswati Shishu Mandir, and urged students to play an active role in nation-building.

Dwivedi called upon young people to focus on three pillars — attitude, adaptability and ability — as India works towards the goal of becoming a developed nation by 2047.

Urging students to become solution providers rather than merely identifying problems, he encouraged them to follow a continuous process of "learn, unlearn and relearn". He also stressed the need for young people to understand emerging technologies while remaining rooted in Indian values.

Dwivedi suggested a daily 'Zero-Ten' routine, asking young people to spend the first 10 minutes of every morning away from mobile phones, using the time to focus on their goals, express gratitude and set their intentions for the day.

The event brought together students, educators, alumni and members of civil society for a synchronised rendition of Vande Mataram. Vidya Bharati Northeast organisational secretary Dr Pawan Tiwari said the national song represented India's cultural unity and highlighted the Northeast's historical and cultural contributions.

Tiwari referred to the spiritual legacy of Maa Kamakhya and Srimanta Sankaradeva, as well as the military history associated with Ahom general Lachit Borphukan, while speaking about the region's place in India's national consciousness. The programme was attended by Air Vice Marshal Sanjeev Bordoloi (Retd), Dr Jagadindra Ray Choudhury, Shishu Shiksha Samiti Assam president Kulendra Kumar Bhagwati, programme coordinator Gaurav Kalita and Assam Gaurav awardee Meenakshi Das, among others.

Speaking to reporters, Vidya Bharati Assam media architect Sailendra Pandey said the collective singing from Assam highlighted the Northeast's role in India's cultural and strategic landscape.

Northeast can emerge as India's 'living lab' for tech, problem-solving: Himanta

Jan Jan Vichar
...✍Guwahati

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma on September 25 said the Northeast can emerge as one of India's "living laboratories" for technology and practical problem-solving, as he launched the North East Seva Innovation Challenge (NESFIC) in Guwahati.

Speaking at the launch of 'NESFIC-Ashtalakshmi for Viksit Bharat', Sarma said the initiative would provide a platform for young people across the region to identify real-world problems and develop solutions that can eventually be implemented. "The Northeast can emerge as one of India's living laboratories for technology and problem-solving. A solution developed for flood management in Assam could potentially find applications in other parts of India, while a low-cost healthcare technology developed for remote communities could serve people far beyond the region," he said. Sarma said NESFIC was not intended to promote innovation merely for creating new products, but to connect young innovators with problems faced by citizens, government departments and industries.

"A startup does not always begin in a large office or a corporate laboratory. It can begin in a hostel room, a college workshop or an institutional laboratory," he said, urging engineering colleges, polytechnics and ITIs across the Northeast to participate in the initiative.

Under NESFIC, 50 real-world challenges have been identified — 40 from government departments and 10 from industry organisations. The challenges are based on problems faced by government departments, industries and citizens. Sarma said one of the key objectives was to create an opportunity for the government to become the first customer for young innovators. He said startups often struggle to enter government markets because conventional procurement requirements include criteria related to turnover, prior experience and bank guarantees. Among the challenges identified by the Health and Family Welfare Department are early detection of pregnancy-induced hypertension, improving access to obstetric ultrasound in remote areas, infection control in labour rooms, faster identification and referral of sick newborns and early detection of congenital deformities.

Will BJP get isolated on Gyanesh Kumar issue? Allies ask CEC to explain his stand

Jan Jan Vichar
...✍New Delhi

Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar must "dispel misgivings in the minds of the people" and clarify the differences in the poll panel over Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls, BJP's allies said on Friday.

The Telugu Desam Party, the Lok Janshakti Party (Ram Vilas), and the Rashtriya Lok Morcha (RLM) issued statements as the Opposition sought answers over the rift in the Election Commission (EC). On September 23, The Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi had objected on record at least 14 times in 10 months to SIR-related decisions taken without their knowledge and glaring gaps in processes.

NDA ally Upendra Kushwaha on Friday called for an immediate clarification from the Election Commission to clear what he described as "confusion" among the public, amid the ongoing controversy over the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls and questions surrounding Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar.



Rashtriya Lok Morcha chief Kushwaha, in a post on X on September 25, said the controversy around SIR had created considerable confusion among people and needed to be addressed. He said the Election Commission should immediately clarify its actual stand so that the confusion is removed.

Kushwaha's statement came a day after he had initially declined to comment on the row when questioned by reporters in Patna. He had then said the issue was related to the Election Commission and that differences of opinion were not unusual, adding that disagreements could happen between individuals.

This comes days after reports highlighted alleged objections by Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi over aspects of the poll panel's functioning, including matters related to electoral rolls and the SIR exercise. The Election Commission has said differences of opinion and internal notes are a normal part of deliberations in a multi-member constitutional body and maintained that its final decisions were taken unanimously.

What Chirag Paswan said?

Kushwaha's demand follows similar remarks by Union Minister and NDA ally Chirag Paswan. On Friday, Paswan said if questions were being raised against the Election Commission, it was the poll panel's responsibility to firmly present its position. He stressed that the matter was not about responding to the Opposition but about maintaining public confidence in the electoral process. "If questions are being raised on the Election Commission, responsibility lies with the CEC to present his stance clearly," Paswan said, adding that it would be problematic if people began doubting the electoral process.

Both Kushwaha and Paswan are allies of the BJP-led NDA in Bihar. Their remarks come amid a broader political debate over the SIR exercise and the functioning of the Election Commission, with Opposition parties also raising questions about the process. The Election Commission has rejected suggestions that internally recorded differences amounted to a breakdown in its functioning, saying discussions and differing views are part of the decision-making process.

Entire nation stands with his family: Sarbananda Sonowal after Indian seafarer dies in Oman vessel attack

Jan Jan Vichar
...✍New Delhi

Suraj Yadav, a wiper from Uttar Pradesh, suffered fatal head injuriesNineteen other Indian crew members were evacuated by the Royal NavySonowal said maritime authorities were told to speed up repatriation

Indian seafarer Wiper Suraj Yadav from Uttar Pradesh died after sustaining head injuries when the Antigua and Barbuda-flagged bulk carrier MV Cape Dao came under a missile attack off the east coast of Oman, Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal said.

Yadav was among 20 Indian seafarers aboard the vessel. The remaining 19 Indian crew members were rescued and safely evacuated by the Royal Navy of Oman and are currently ashore, Sonowal said.



Expressing condolences over Yadav's death, Sonowal said the country stood with his family in their hour of grief.

"Entire nation stands with his family in this hour of grief," Sonowal said in a post on X.

The minister said directions had been issued to maritime authorities to coordinate with Omani authorities and the ship management company for the immediate and safe repatriation of the surviving crew members.

"Directions have been issued to maritime authorities to coordinate closely with Omani authorities and the ship management company to ensure the immediate and safe repatriation of our surviving crew," he said.

Sonowal also said the government would ensure that Yadav's mortal remains were brought back to India with full dignity and that all possible assistance was extended to his family.

The Ministry of External Affairs (MEA) separately condemned the attack on MV Cape Dao and expressed concern over continuing attacks on commercial shipping in the region.

"We condemn the attack on the commercial vessel MV Cape Dao earlier today off the east coast of Oman," the ministry said in a statement.

The MEA confirmed that 19 of the 20 Indian seafarers aboard the vessel had been rescued, while one Indian national had died.

The attack adds to growing security concerns for commercial shipping operating through the region, with the safety of seafarers remaining a key concern.

EDITORIAL

Vande Mataram and the Freedom of Conscience

The Supreme Court's intervention in the debate over compulsory singing of Vande Mataram has brought an important constitutional principle back into focus: patriotism cannot be enforced by punishment. Vande Mataram occupies a revered place in India's freedom struggle and remains the national song. Its historical contribution to the national movement deserves respect. At the same time, respect for a national symbol does not necessarily mean that every citizen must express that respect in an identical manner. The Supreme Court's reference to its 1986 judgment on the national anthem is significant. In that case, the Court recognised that a citizen could respectfully refrain from singing the anthem on grounds of conscience without being subjected to criminal action. The same constitutional reasoning becomes relevant when questions arise over religious belief, freedom of expression and individual conscience.

India's strength lies in accommodating differences rather than demanding uniformity. Articles 19 and 25 of the Constitution protect freedom of expression and freedom of conscience and religion, subject to constitutionally permitted restrictions. These freedoms are meaningful only when they also protect unpopular or minority choices.National symbols should unite citizens, not become instruments for testing their patriotism. A person who refuses to sing a song for reasons of conscience need not be treated as someone who rejects the nation. The Supreme Court's decision to examine the legal protection available to such citizens is therefore an important reminder that constitutional patriotism is built on liberty, dignity and equal citizenship-not compulsion.

Why 100% Tariffs on India, China Unlikely

Jan Jan Vichar

...✍Sunanda K. Datta-Ray

By so expeditiously signing the Russia sanctions bill into law, US President Donald Trump appears to have paved the way for up to 100 per cent tariffs on countries buying Russian oil and gas, putting India and China under threat. But that need not mean that a huge hike in tariffs is imminent. We know from experience that Mr Trump's bark is often worse than his bite. Moreover, not for nothing has diplomacy been called a feminine art involving a great deal of delicately suggestive moves and contortionist footwork. This is where the comparison/contrast between a diplomat and a lady comes in. As an old English saying has it, if a diplomat says "yes", he means "maybe", if he says "maybe" he means "no", and if he says "no" he's no diplomat. If a lady says "no" she means "perhaps", when she says "perhaps" she means "no", and if she says "yes", she is NO LADY! Or to be candid, can people who ride roughshod over their own high-falutin' rules when it comes to making a fast buck (as the American slang has it) be called gentlemen? The United States' imports from Russia were valued at $4.05 billion during 2025, according to the United Nations COMTRADE database on international trade. Such heavy purchases deprive Mr Trump of the moral right to point any kind of accusing finger at anyone else who tries to follow the same path.

The "Lindsey O Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026", as the new US measure named after the late Senator Lindsey Graham - one of Ukraine's staunchest defenders in Washington who died in July this year shortly after returning from a trip to Kyiv - is no exception. But although Mr Trump's nod came only two days after the Republican-led House of Representatives passed the sweeping sanctions bill by a vote of 262-159 following no less than 17 months of discussions on Capitol Hill, even that may not signal immediate and dire follow-up action.

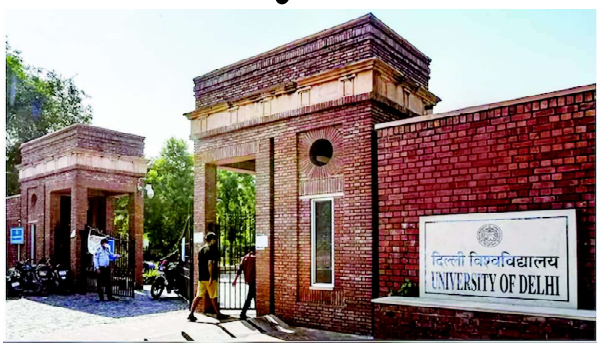
For one thing, even after Mr Trump's signature, the bill doesn't automatically target India even if we are the second biggest buyer of Russian oil and gas. Secondly, even if it did, 100 per cent is the upper limit of the punitive tariff that can be imposed, it is not the new default tariff. The intention of the US legislation is to reduce the financial resources sustaining Russia's war against Ukraine. It targets Russian officials, banks, energy interests, and foreign entities supporting Moscow's military operations. The law authorises Mr Trump to impose tariffs on countries doing business with Russia in order to cut their dependence on Russian oil and gas.

According to the US House Ways and Means Committee, the legislation directs tariffs of up to 500 per cent on Russian goods. It also provides for duties of up to 100 per cent on goods from countries covered by its Russian oil and gas purchase provisions - which cover major Russian energy importers and leading facilitators of oil sanctions evasion. Additionally, the bill includes sanctions against the Russian President, Vladimir Putin, personally, as well as against other senior figures in the Kremlin regime. Undeniably, India faces a new tariff threat now that Mr Trump has signed the Russia sanctions bill into law. An amendment introduced by Democratic Congressman Steny Hoyer had called for explicitly naming 10 nations-starting with India, but including China, the UAE, Turkey, Singapore, Azerbaijan, Kazakhstan, Hungary, Kyrgyzstan and Slovakia - to be eligible for tariffs of up to 100 per cent under the bill's secondary tariff provisions. However, the amendment does not itself impose a 100 per cent duty on India. The tariffs could be imposed on India only if Trump chooses to exercise his power under the new law. If he does do so and levies the 100 per cent tariff on India, it would be on top of a 10 per cent tariff that the US currently imposes on imports from New Delhi as a penalty for allegedly not doing enough to stop the import of goods made using forced labour. However, the exact impact of new tariffs on Indian exports can be assessed only after the US announces the tariff rates. Despite all that we are told at home by various levels of official and semi-official spokesmen about how hunky-dory relations are between those best of global chums, Narendra Modi and Vladimir Putin, ties between India and the US were strained last year when Mr Trump imposed an additional 25 per cent tariff on Indian imports of Russian crude, on top of a 25 per cent reciprocal tariff. But better sense prevailed in the Kremlin and the damaging impact wasn't long-lived. The additional tariffs were removed in February 2026, while the reciprocal tariff was reduced to 18 per cent as part of a slightly more relaxed US-India trade framework. Perhaps this was in recognition of the fact that India had made it abundantly clear when the US Congress passed the Russia sanctions bill that it is determined to take all necessary measures to protect its trade and economic interests. "As stated on several earlier occasions, India remains firmly committed to ensuring energy security for its 1.4 billion people. It will continue to do so through diversified sourcing and based on evolving market dynamics," declared an external affairs ministry statement. According to the external affairs ministry, the issue of India's oil trade with Russia has been discussed at high levels in recent months with various US interlocutors. "Its potential implications for not just the bilateral relationship but also the international energy market has been very clearly articulated by the Indian side," the ministry said. While most Republican lawmakers supported the legislation, privately, many urged party leaders to take out new tariff powers from the bill, reported CNN.

According to media reports, they warned that the tariffs could further hike prices. That is also something for Mr Trump to bear in mind. But the guessing seems to be that he is possibly looking for some advantage in the long-protracted negotiations over a bilateral India-US trade agreement. Some form of transactional advantage also often passes for diplomacy

From Rs 150 in 1947 to powerful student body: The story of DUSU's rise

Jan Jan Vichar
...✍New Delhi



The union's initial years were not easy, particularly when it came to finances. On March 27, 1953, the university's Executive Committee considered a request from the University Students' Union for financial assistance.

The university noted that Rs 500 had already been given to the union during that year and said it should work towards becoming financially self-sufficient. A year later, the financial gap had become more visible. Records from March 14, 1954, showed that the union had spent Rs 1,995 against an income of Rs 815. The same records noted that DUSU had received a constitution and had conducted elections for the first time.

A caretaker committee was proposed to manage its affairs until the following academic year, while additional spending was to be restricted. A grant of up to Rs 1,100 was also proposed to cover expenses that had already been incurred, subject to approval of the bills.

A new constitutional structure in 1973 DUSU's organisational structure came under fresh consideration nearly two decades later. On August 2, 1973, the Executive Council considered scrapping the existing constitution and introducing an interim constitution for the union. The new framework brought in financial controls.

Initially, spending above Rs 100 required approval from the union's Executive Committee. It also defined the administrative roles within DUSU. The Delhi University vice-chancellor was designated as the union's patron, while a staff adviser and treasurer were to be appointed from the university's teaching faculty and by the patron.

The constitution provided for four elected office-bearers: president, vice-president, secretary and assistant secretary. These positions were to be directly elected by DUSU members. What are the key posts in DUSU? The four central positions in the DUSU election are president, vice-president, secretary and joint secretary. The president serves as the union's main representative, while the vice-president performs the president's duties in their absence. The secretary handles the union's administrative work, while the joint secretary has responsibilities related to communication, events and student grievances under the current structure.

The current DUSU constitution also places the vice-chancellor of Delhi University in the role of patron and sets out the union's objectives, including representing students before university authorities and promoting student welfare. How much does DUSU membership cost?

The subscription fee for DUSU remained relatively low for decades. Students paid Rs 5 until the 2012-13 academic year. The fee was increased to Rs 20 in 2013-14 and was later raised to Rs 40 on June 21, 2024, according to university officials cited in reports. DUSU elections become a major campus event Over the decades, DUSU elections developed into a major event in Delhi University's political and campus life.

The union's elections have traditionally involved student groups with links to larger political organisations, including the ABVP and NSUI, as well as Left-backed student groups and independent candidates. The 2026 election was contested for the four central posts, with ABVP, NSUI and the AISA-SFI alliance among the major groups in the contest. Voting took place on September 18, while counting began at 8 am on September 19 at the Multipurpose Hall of the University Sports Stadium in North Campus.

The election recorded a voter turnout of 40.46%. What issues dominated the 2026 DUSU election? Student safety, affordable accommodation and campus facilities were among the major issues raised during the 2026 campaign. The collapse of a five-storey building housing a boys' PG in south Delhi's Satya Niketan, which killed seven people, including students, also brought student accommodation and safety into sharper focus. Candidates and student groups also raised issues related to transport, campus infrastructure and security.

Who contested the 2026 DUSU election?

ABVP fielded Yash Dabas for president, Ishu Maurya for vice-president, Riya Chhawadi for secretary and Lakshya Raj Singh for joint secretary. NSUI nominated Vijay Shankar Meena for president, Vir Chatrath for vice-president, Namrata Chaudhary for secretary and Gopal Choudhary for joint secretary.

The AISA-SFI alliance fielded Ananya Raturi for president, Akshat Shikhar for vice-president, Stanzin Deskyong for secretary and B Parijaat for joint secretary. As counting progressed on September 19, the four races saw changing leads, reflecting a closely watched contest. From a Rs 150 proposal to a nationally watched election DUSU's journey reflects how student representation at Delhi University has changed over nearly eight decades.

What started in 1947 with a proposal for a student union and a possible Rs 150 grant gradually developed into a structured elected body with multiple office-bearers, a formal constitution and representation across the university. Today, DUSU elections attract attention well beyond the university campus, with student organisations using the contest to raise issues concerning education, safety, accommodation and student rights.

CBSE : Class 10, 12 Students Await Exam Schedule

New Delhi: Students appearing for the Central Board of Secondary Education (CBSE) Class 10 and Class 12 board examinations in 2027 are awaiting the release of the official date sheet. As of now, CBSE has not announced the timetable or confirmed the date on which the subject-wise schedule will be released. The official date sheet is expected to be published on the CBSE website, cbse.gov.in, once it is finalised. The release pattern of previous years suggests that the CBSE Class 10 and 12 date sheet for 2027 could be announced in the latter part of 2026. However, students should note that this is an expectation based on earlier schedules and not an officially confirmed release date.

For the 2026 board examinations, the final date sheet was reportedly issued on October 30, 2025, following a tentative schedule released on September 24, 2025. For the 2025 examinations, the timetable was released on November 20, 2024, while the 2024 schedule was announced on December 12, 2023. The 2027 CBSE board examinations are expected to follow the traditional academic calendar, with examinations likely to be conducted during February and March 2027. The exact dates, however, will only be known after CBSE publishes the official timetable.

Hanuman Ansh: Refused to Leave the Box Office

Jan Jan Vichar
...✍New Delhi

Some films arrive with hundreds of crores behind them. Hanuman Ansh arrived with an estimated budget of just Rs 2 crore-and refused to leave. In an industry where expensive productions, established stars and massive promotional campaigns often dominate the box-office conversation, this modestly made film has quietly produced one of the year's most striking theatrical stories.

Directed by Vishal Chaturvedi and starring Shobhinav Satya in the lead, Hanuman Ansh has completed 47 days in cinemas. According to the figures cited in the report provided, the film has accumulated around Rs 279.07 crore in reported net box-office collections, while its reported gross collection has reached approximately Rs 329.54 crore.

The contrast is what makes the numbers remarkable: a film reportedly made for around Rs 2 crore has generated a reported net collection that is many times its production budget. But the film's biggest achievement may not be the number itself. It is the fact that it managed to survive long enough to reach this stage.

From Slow Starter to Long-Running Release

The film's subject may have played an important role in creating this sustained interest. Hanuman Ansh is based on the life of Neem Karoli Baba, giving the film a spiritual and devotional dimension. Rather than relying entirely on the conventional ingredients of a big commercial release, the film appears to have connected with an audience interested in its subject. Its journey also illustrates the importance of audience response after the opening weekend. A film may begin quietly but can continue to grow if viewers recommend it to others and maintain interest over several weeks. That appears to have been the case with Hanuman Ansh, according to the figures cited in the report.

When Bigger Films Could Not Push It Aside

The film's endurance becomes even more notable when viewed against the competition it faced. During its run, several new and larger films entered theatres. Yet Hanuman Ansh continued to retain audience attention instead of disappearing after the arrival of fresh releases. That is unusual in a theatrical market where screen space is constantly contested and new releases can quickly replace older films. The film's ability to remain in the conversation for more than six weeks therefore becomes a story in itself.

The film now stands at the doorstep of another major box-office landmark. At a reported Rs 279.07 crore net, Hanuman Ansh is around Rs 21 crore away from Rs 300 crore. If its pace remains strong enough, the film could potentially reach the milestone during its current theatrical run.



The Film Was Almost Out of the Race

The early days of Hanuman Ansh gave little indication of what was to come. The film reportedly had a sluggish first two weeks. With bigger releases waiting to arrive, its theatrical run appeared vulnerable. In normal circumstances, a low-budget film struggling in its opening phase can quickly lose screens and audience attention. Yet Hanuman Ansh did something unexpected. Instead of disappearing from theatres, the film began finding an audience. Its momentum reportedly improved from the third week, changing the trajectory of its theatrical run. That turnaround is now one of the most interesting parts of the film's story.

47th Day: The Numbers Still Refuse to Slow Down

The film's 47th day is particularly significant. According to the supplied figures, Hanuman Ansh collected approximately Rs. 3.04 crore on its 47th day, taking its cumulative reported net collection to Rs 279.07 crore. Its reported gross collection has already crossed the Rs 329-crore mark. For a film that started with an estimated Rs 2-crore production budget, the scale of this reported theatrical performance is extraordinary. The next major target is now clearly visible: Rs. 300 crore in net collections. The film needs roughly another Rs 21 crore to reach that figure. Whether it achieves the milestone will depend on how its collections behave in the coming days, but its 47-day run has already given it an unusually long theatrical life.

The Power of a Film Finding Its Audience

The Hanuman Ansh story also raises a broader question about the changing nature of the theatrical business. For years, box-office expectations have often been associated with production scale, star power and marketing budgets. Those factors remain important, but films occasionally demonstrate that audience connection can take an unexpected route. A smaller film with a relatively unfamiliar cast can find space if its subject resonates with viewers. In the case of Hanuman Ansh, its spiritual theme, connection with Neem Karoli Baba and reported word-of-mouth response appear to have helped it remain relevant far beyond its initial theatrical window.



Printed & Published by Purvanchal Prints, GMCH Road, Harbala Market, Bhangagarh, Guwahati-781005 Contact: 69001 26012
Email : Official.janjanvichar@gmail.com,Website : www.janjanvichar.in ● Executive Editor : Subhash Kumar Choudhary ● Editor : Dhaneshwar Choudhary